

रीवा इंदौर के बीच 72 सीटर हवाई सेवा शुरू

इंदौर: मध्य प्रदेश के रीवा के साथ ही विद्युतासियों के लिए सोमवार का दिन बेहद खास रहा, क्योंकि रीवा से इंदौर के लिए हवाई सेवा के रूप में एक और सीधात मिली है। एटीआर विमान ने सोमवार को यात्रियों को लेकर रीवा एयरपोर्ट सेइंदौर के लिए उड़ान भरी। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल और नारीय विकास आवास मंत्री कैलाश विजयरामीय की मौजूदगी में, रीवा इंदौर विमान सेवा की शुरुआत हो गई। रीवा सेइंदौर हवाई सेवा विन्ध्य क्षेत्र की कनेक्टिविटी को नई गति देगा और विकास, व्यापार और पर्यटन के अवसरों को सशक्त बनाएगा।

विध्य क्षेत्र के लोगों के लिए सोमवार का दिन ऐतिहासिक सांवित्र हुआ, रीवा एयरपोर्ट सेइंदौर और रीवा के बीच सीधी हवाई सेवा शुरू हो गई है। इंडिगो एयरलाइंस द्वारा संचालित इस 72सीटर प्लाइट के शुरू होने से यात्रियों को बड़ी राहत मिली है। अब ट्रेन या बस से करीब घंटे में पूरी होने वाली यह यात्रा दो घंटे से भी कम समय में पूरी हो सकेगी। पहली दिन इस उड़ान की सभी सीटें फूल रहीं, जिससे साफ है कि इस रुट पर यात्रियों की भारी मांग है।

कड़ा के की ठंड से रकूल बंद

उत्तर भारत में बढ़ती ठंड और शीतलहर के बीच स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर प्रशासनिक सख्ती देखने की मिल रही है। कई राज्यों के स्कूलों में हृद्दृष्टि का ऐलान किया गया है। वहाँ क्रिसमस नजदीक आते ही देश के कई राज्यों में स्कूल हृद्दृष्टि को ऐलान किया गया है। वहाँ क्रिसमस नजदीक आते ही देश के कई राज्यों में स्कूल हृद्दृष्टि को ऐलान किया गया है। कुछ राज्यों नेतृत्वी विंटर वेकेशन का ऐलान किया है, तो कुछ नेपरंपरा सेहटकर

स्कूल खुले रखने का फैसला लिया है। दिल्ली में जहाँ क्रिसमस की हृद्दृष्टि का ऐलान किया गया है। वहाँ यूपी में इस बार परंपरा टूटने जा रही है।

दिल्ली में दिसंबर को क्रिसमस के अवसर पर स्कूल बंद रहेंगे। वहाँ खंडिल दिसंबर को रिस्ट्रेक्टेड हॉलिडे घोषित किया गया है, यानी स्कूल प्रबंधन अपनेस्तर पर फैसला लेसकता है। अधिकतर स्कूलों के पूरी तरह बंद रहनेकी संभावना है।

कोडीन सिरप मामले में सीएम योगी का सपा पर हमला, विधानसभा में तीखी बहस



लखनऊ: कोडीन युक्त कफ सिरप की अवैध तस्करी के मामले को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को उत्तर प्रदेश विधानसभा में विपक्ष, विशेषकर समाजवादी पार्टी (सपा), पर तीखा हमला बोला। चर्चा के दौरान उन्होंने इस प्रकरण में गिरफ्तार आरोपियों और उनके कथित राजनीतिक संबंधों का उल्लेख किया।

मुख्यमंत्री ने बताया कि इस मामले में पकड़े गए आरोपियों में बर्खास्त पुलिसकर्मी आलोक भी शामिल हैं। उन्होंने दावा किया कि आरोपी अमित सिपाही का समाजवादी पार्टी से संबंध रहा है और उसकी फोटो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ मौजूद है, जिसे उन्होंने सदन में दिखाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मामले में माफिया से किसके संबंध हैं, यह प्रदेश की जनता जानती है। सीएम योगी ने आरोप लगाया कि मुख्य आरोपियों में शामिल शुभम जायसवाल के भी सपा से संबंध रहे हैं। उन्होंने कहा कि शुभम जायसवाल, अमित यादव का कारोबारी साझेदार है, जो वाराणसी कैंट से सपा का प्रत्याशी रह चुका है। इसके अलावा उन्होंने मिलिंद यादव का भी नाम लिया और कहा कि वह शुभम जायसवाल का करीबी है। मुख्यमंत्री के अनुसार, मिलिंद यादव का फोन नंबर एक कर्फ के जीएसटी पंजीकरण में दर्ज है।

इस दौरान समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने लगातार विरोध दर्ज कराया और सदन में हँगामा होता रहा। शोर-शराबे के बीच मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मामले में किसी भी दोषी को बक्शा किया गया है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश इस मामले में देश का पहला राज्य है,

जहाँ बड़े पैमाने पर कार्रवाई की गई है। उन्होंने बताया कि फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FSD) ने अब तक पृष्ठ दुकानों पर छापेमारी की है, जिनमें से कम प्रतिष्ठानों पर एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। अब तक आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि अन्य की तलाश जारी है।

सीएम ने स्पष्ट किया कि प्रदेश में कफ सिरप से किसी की मौत नहीं हुई है, हालांकि राज्य के बाहर इसके दुरुपयोग से मौत के मामले सामने आए हैं। उन्होंने बताया कि वाराणसी, सहारनपुर, गाजियाबाद, कानपुर और लखनऊ के कई थोक विक्रेताओं के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। अब तक एक हजार से अधिक सिरप नमूनों की जांच की जा चुकी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ लोग नशे और मनोरंजन के लिए कफ सिरप का दुरुपयोग करते हैं, जिसे किसी भी स्थिति में बदाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने दोहराया कि इस मामले की गहन जांच की जा रही है और एक भी अपराधी बचने नहीं दिया जाएगा।

AAP का आरोप: आदिवासी फंड से पीएम मोदी की रैलियों पर करोड़ों रुपये



खर्चों का पूरा विवरण सार्वजनिक किया गया, जहाँ किसी तरह की सुरक्षा आपत्ति नहीं जाती है।

AAP सांसद संजय सिंह ने इस मुद्दे पर एक वीडियो साझा करते हुए कहा कि आदिवासी क्षेत्रों में लगभग हजार बच्चे कुपोषण का शिकार हैं। उनके अनुसार, बच्चों के पोषण, अस्पतालों और स्कूलों के निर्माण के लिए निर्धारित फंड को प्रधानमंत्री की

रैलियों में खर्च किया गया।

संजय सिंह ने सवाल उठाते हुए कहा कि जब विधायकों ने सरकारी अधिकारियों से कुपोषण दूर करने के लिए फंड की मांग की, तो जबाब मिला कि सरकार के पास पैसा नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि वही पैसा प्रधानमंत्री की रैलियों पर खर्च किया जा रहा है।

बिहार के मुख्यमंत्री को हो सकती है जेल?



Ali Aadil Khan
Editor

अली अदिल खान

बिहार के मुख्यमंत्री नितीश कुमार की तबीयत ख़राबी की ख़बरें और Visuals सामने आते रहे हैं, लेकिन वो इन्हें बीमार हैं की महिलाओं के हिजाब खींचने लग जाएंगे ऐसा प्रदेश और मुल्क की अवाम की सोच से भी परे की बात है। सड़क के गुंडे मवाली भी इस तरह की हरकत करते वक़्त लोगों की नज़र से बचने की कोशिश करते हैं। और यहाँ यह हरकत स्टाफ, जनता और मीडिया के सामने किये जाने को कोई बीमारी ही कहा जाएगा, अब चाहे वो शारीरिक हो या वैचारिक। अब इस घिनौने घटना कर्म के तीन हिस्से हैं, अगर यह शारीरिक बीमारी का असर है उनको तुरंत रिटायरमेंट लेना चाहिए, वैचारिक बीमारी का असर है टोपी लगाने की साज़िशी सियासत से बाहर रहना चाहिए और अगर यह एक महिला को अपमानित करने की नीयत से किया गया था तो इसपर उनको सजा के लिए तैयार

रहना चाहिए।

इस तरह के मामले में सबसे प्रत्यक्ष और प्रमुख धारा है। 'शील भंग' (Modesty Outraging) में महिला के शरीर या वस्त्रों के साथ ऐसा कोई भी कृत्य शामिल है जिससे उसकी गरिमा को ठेस पहुँचती है। क्योंकि किसी महिला के हिजाब या साड़ी को जानबूझकर खींचना एक गंभीर अपराध है, जिसके लिए IPC की धारा 354 और/या धारा 354B के तहत एक साल से लेकर सात साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता है।

हालांकि यह बात तय है कि जब तक वो वर्तमान सत्तारूढ़ पार्टी के सहभागी हैं तब तक तो वो सरकार की नज़र में दूध के धुले हैं लेकिन जैसे ही समर्थन वापस लेते हैं तुरंत उनके खिलाफ इसी केस में PIL डालकर स़द्भूत हो सकती है।

लेकिन उनकी बीमारी भी इन्हीं समझदार है कि कोई ऐसा काम नहीं कराएगी जिससे वो सत्ता से बाहर आजायें। अब वो हर हाल में केंद्र सरकार के समर्थन में रहकर ही अपना

समय पूरा करना मुनासिब समझेंगे।

नितीश कुमार जो जन सेवक के रूप में अपना कार्य कर रहे हैं उनके द्वारा की गई यह घटिया हरकत सिर्फ़ एक घटना नहीं है बल्कि यह संवेदनशील मर्यादा, महिला सम्मान और व्यक्तिगत आज़ादी पर गंभीर चोट है जो सरकार की संवेदनशीलता और निष्पक्षता पर बड़ा सवाल खड़ा करता है।

बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा एक महिला डॉक्टर के हिजाब को सार्वजनिक मंच पर हटाना किसी भी तरह से स्वीकार नहीं किया जा सकता। अगर

Deputy CM उनको पीछे से न रोके होते तो शायद वो पूरा हिजाब ही खींच सकते थे। हालांकि उनकी बॉडी लैंग्वेज से उनके मानसिक असुंतलन का आभास तो हो रहा था। और इसी ग्राउंड पर इनको माफ़ी मिल सकती है अन्यथा सीधा जेल का प्रावधान है, अगर अदालत चाहे तो। बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री की मंशा चाहे कुछ भी रही हो, किन्तु किसी महिला की सहमति के बिना उसके पहनावे को छूना वह भी सत्ता के सर्वोच्च पद पर बैठकर, न सिर्फ़ अमानवीय

और अनुचित है, बल्कि लोकतांत्रिक आचरण और देश के क्रानून के भी ख़लिफ़ है।

इस घटना के बाद अब देश की जनता को यह तय करना होगा कि महिलाओं का सम्मान कोई नारा नहीं, बल्कि उनका बुनियादी अधिकार है। और धार्मिक पहचान चाहे वह किसी भी मज़हब की हो निजी मामला है, राजकीय सरकारी मंच के उच्चतम पद पर बैठकर ऐसा नफरती प्रदर्शन शायद देश की पहली घटना है।

सवाल सिर्फ़ एक नेता के व्यवहार का नहीं, सवाल उस सोच और मानसिकता का है जो सत्ता में बैठकर व्यक्तिगत सीमाओं को लांघने को अपना अधिकार मान बैठी है।

आज ज़रूरत इस तरह की घटनाओं पर सफाई देने की नहीं बल्कि संवेदनशीलता, जवाबदेही और सार्वजनिक माफ़ी को सुनिश्चित करने की है। क्योंकि लोकतंत्र में सत्ता क्रानूनी दायरे में रहकर ही सम्मानीय हो सकती है, किसी नागरिक की गरिमा, सम्मान और अधिकारों से बढ़कर नहीं।

किसी महिला के हिजाब या साड़ी को जानबूझकर खींचना एक गंभीर अपराध है, जिसके लिए IPC की धारा 354 और

मध्यप्रदेश विधान सभा का एक-दिवसीय विशेष सत्र विकास को समर्पित प्रदेश के विकास का पथ सबके विचारों से निर्धारित करने का आयश्वासन

एल.एस. फरदेनिया

मध्यप्रदेश विधानसभा का एक-दिवसीय विशेष सत्र विकास का पथ सबके विचारों से निर्धारित किया गया। यह सत्र दो उद्देश्यों से बुलाया गया था। पहला था मध्यप्रदेश विधानसभा कानून वर्ष पूर्ण होना और दूसरा खब्बत तक मध्यप्रदेश के विकास पर एक विजन डाक्यूमेंट पर चर्चा करना। विधानसभा के विशेष सत्र को संबोधित करते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि विजन डाक्यूमेंट सत्ताधारी विधायकों विचारों पर आधारित तो होगा ही परंतु प्रतिपक्ष के विचारों को भी महत्व दिया जाएगा। मध्यप्रदेश के विकास का पथ सबके विचारों से निर्धारित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने भी इसी तरह की इच्छा प्रकट की और मध्यप्रदेश के विकास से संबंधित कुछ मुद्दे खेले।

खास बात यह थी कि विशेष अधिवेशन में भाषण देने वाले के विधायक संतानाधारी दल के थे और क्वार्टिपक्ष के। दोनों पक्षों के विधायकों ने अपने-अपने विचार प्रकट किए। विधानसभा में ब-भ से लेकर अभी तक राज्य के जितने मुख्यमंत्री रहे, उनके योगदान पर विशेष चर्चा की गई। इन मुख्यमंत्रियों में कांग्रेस के रविशंकर शुक्ल, मंडलोई, कैलाशनाथकान्तर्जु, द्वारका प्रसाद मिश्र, गोविन्द नारायण सिंह आदि शामिल थे। भाजपा (पूर्व में जनसंघ) के जो

कॉलेजों के विद्यार्थियों के लिए खेला जाता है और ऐसा यह पहली बार है कि विवर आम जनता के बीच में भी खेला गया है। इस विवर को आम लोगों के बीच में प्रचारित करने के लिए समाचार पत्रों में बड़े-बड़े विज्ञापन छपे हैं। दूसरी इस विवर से यह जानकारी ली गई है कि मध्यप्रदेश कब बना था? कौन उसके पहले राज्यपाल थे? कौन उसके पहले मुख्यमंत्री थे। कौन विधानसभा के सदस्य थे? आदि

विवर के माध्यम से आम जनता से इस तरह की जानकारी मांगी गई। इसका उद्देश्य साफ़ है कि लोगों को यह पता लगे कि पहले मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री रविशंकर शुक्ल थे। जो सिर्फ़ एक महीने मुख्यमंत्री रहे और जिनकी अचानक दिल्ली में हृदयगति रुकने से मर्त्यु हो गई। फिर यह बताया गया है कि मध्यप्रदेश का राज्यपाल कौन थे? फिर बताया जाता है कि डॉ. पट्टाभिसीतारमैया। डॉ. पट्टाभिसीतारमैया ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए सुभाषचंद्र बोस के खिलाफ़ चुनाव लड़ा था। वो चुनाव में हार गए थे। जब चुनाव का परिणाम घोषित हुआ तो महात्मा गांधी ने कहा कि डॉ. पट्टाभिसीतारमैया की हार मेरी हार है। डॉ. पट्टाभिसीतारमैया का बहुत बड़ा योगदान यह है कि उन्होंने कांग्रेस की अधिकृत जीवनी लिखी है अर्थात् कांग्रेस का इतिहास लिखा है।

इसके साथ ही विधानसभा भवन में एक

प्रदर्शनी लगाई गई है जिसमें से लेकर आज तक मध्यप्रदेश की विकास यात्रा को दिखाया गया है। जिसको काफ़ी लोग देखने आए और मध्यप्रदेश के इतिहास को समझे। मिंटों हाल का भी अपना एक इतिहास है। भोपाल इसलिए ही चुना गया कि मिंटों हाल के समान एक बड़ा कक्ष मध्यप्रदेश में कहीं और उपलब्ध नहीं है। मिंटों हाल को पहली विधानसभा के रूप में उपयोग किया गया था। मिंटों हाल तत्कालीन वायसराय गवर्नर जनरल जब भोपाल आए तो उनके सम्मान में बनाया गया था। इस कक्ष में इतनी जगह थी कि यह पहली विधानसभा का अधिवेशन इसमें किया गया था। प्रथम अधिवेशन में गवर्नर ने अपने उद्घाटन भाषण में यह दावा किया था कि नए राज्यों का निर्माण अत्यधिक शांतिपूर्ण ढंग से हुआ। गवर्नर के इस भाषण को चुनौती दी थी विश्व अधिवेशन में गवर्नर ने उन जिलों में जहां वो रहते हैं और उन्हें जिस जिले के प्रभारी बनाया गया है वहां जाकर बताएं कि उन जिलों में क्या-क्या कार्य हुए हैं। मिंटों के अलावा विधानसभा के विधायकों और पार्टी के नेताओं को भी आदेश दिया गया कि वे गत गांव में गुजारें। उनके दावों को कांग्रेस ने लगभग गलत बताया। कांग्रेस ने कहा कि ये सब गुब्बारे हैं जिन्हें फोड़ा जा सकता है। यह एक संयोग है कि कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी ने भी अपने कार्यकाल के दो साल इसी माह पूरे किए हैं।

के लिए पुलिस को गोलियां चलानी पड़ीं। यहाँ तक कि होटल में बैठे लोगों पर भी गोलियां चलीं। कई स्थानों पर गोलियां चलीं। इसलिए सीधी तिवारी ने कहा कि यह कहना उचित नहीं है कि राज्यों का निर्माण बना खून-खराबे के हो रहा है। जो कार्यक्रम आयोजित किए गए उनमें मुख्यमंत्री ने अपने दो साल के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनायीं। शिक्षा के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, विजली के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में व्यावरण के क्षेत्र में बनाया गया था। मुख्यमंत्री ने भोपाल के लगभग सभी अखबारों को इंटरव्यू दिए और स्वयं अपने द्वारा किए गए विवरास से खासकर उद्योगों में निवेश को लोगों को समझाया। बहुत सारी सूचनाएं दी गईं। उसके बाद उन्होंने अपने मंत्रियों से कहा कि वे पूरे प्रदेश में जाकर अपने-अपने जिलों में जहां वो रहते हैं और उन्हें जिस जिले का प्रभारी बनाया गया है वहां जाकर बताएं कि उन जिलों में क्या-क्या कार्य हुए हैं। मंत्रियों के अलावा विधानसभा के विधायकों और पार्टी के नेताओं को भी आदेश दिया गया कि वे गत गांव में गुजारें। उनके दावों को कांग्रेस ने लगभग गलत बताया। कांग्रेस ने कहा कि ये सब गुब्बारे हैं जिन्हें फोड़ा जा सकता है। यह एक संयोग है कि कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी ने भी अपने कार्यकाल के दो साल इसी माह पूरे किए हैं।

Russia urges IAEA to keep its inspection into Iranian nuclear programme within neutral, apolitical framework

Cairo: Russia's Foreign Minister Sergey Lavrov has urged UN's nuclear watchdog chief, Rafael Grossi, to keep the International Atomic Energy Agency's (IAEA) investigation into Iran's nuclear programme within a balanced, neutral, non-political, and impartial framework, saying any renewed cooperation must be on mutually acceptable terms.

"We call on IAEA Director General Grossi, who is pushing to restore contacts with Tehran, to strictly adhere to the founding mission of the IAEA Secretariat," Lavrov told the media in Cairo on Friday, reports TASS today.

"This includes the neutral, unbiased, and professional nature of assessments and the broader activities of this organisation," Lavrov added.

Iran and the International Atomic Energy Agency (IAEA) have found each other at loggerheads in the past six months, before reaching an uneasy technical understanding in the Egyptian capital in September, after Egypt mediated a deal between Tehran and the IAEA, geared towards the gradual restoration of the UN nuclear watchdog's access for inspecting its nuclear sites.

Following the reimposition of all pre-2015 international sanctions on Tehran back in September, Iranian Foreign



Minister Abbas Araghchi deplored the move, claimed that the US and the E-3 nations had "killed" the Cairo nuclear agreement through its hostile actions.

Lavrov, commenting on the recent tussle between Tehran and Vienna, said that Iran could not be expected to resume full cooperation on fair terms, while being cornered into a wall and being bombed with economic and political sanctions.

"Moscow backs efforts to resume talks between Iran and the IAEA, but only on a fair basis that Tehran views as balanced and consistent with the agency's mandate," he added.

The IAEA Board of Governors adopted a Western-backed resolution last month, urging Iran to provide full access and information about its atomic research project, with diplomats noting that the measure was passed by a massive margin, with 19 votes in favour, 12 abstentions, and only three against, with Russia, China, and Niger voting against it.

The resolution called on Iran to allow verification of its enriched uranium stockpile and inspections at sites damaged by US and Israeli airstrikes in June.

Accusing the US of trying to achieve through diplomacy what it could not

gain by military force, he criticised Washington's demands, stating "They want us to accept zero enrichment and limits on our defence capabilities, adding "This is not negotiation."

"This is dictation" Trump had previously said that Iran could avoid its past mistakes and further tensions by reaching a deal, adding that any attempt to revive its nuclear programme without an agreement would prompt further US action, remarking that it missed a chance earlier though the table remains open.

Iran denies seeking nuclear weapons and claims its nuclear programme is for peaceful purposes, though this has been heavily disputed by the US, Israel, EU, and NATO states, citing Tehran's extremely high levels of uranium enrichment which far exceed levels needed for civilian use.

Also refusing to hold talks with Washington over Tehran's nuclear programme, Iran's Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei, in a flat-out rejection of US demands for curbing uranium enrichment and its rebuilding its missile capabilities, mocked US President Donald Trump, saying that dealing with him was beneath the dignity of the Islamic Republic.

US Forces Seize Second Oil Tanker Near Venezuela

Washington: US Secretary of Homeland Security Kristi Noem said on Saturday that US forces seized another oil tanker off the coast of Venezuela earlier in the day.

According to Noem, the US Coast Guard, with support from the Department of Defense, intercepted the tanker in a pre-dawn operation on December 20. She said the vessel had last docked in Venezuela.

This marks the second such seizure in recent weeks. On December 10, US forces detained an



other oil tanker near Venezuela, a move that the Venezuelan government condemned as "theft" and a violation of international law, according to Xinhua News Agency.

US President Donald Trump has announced

a blockade of oil tankers subject to US sanctions that are traveling to and from Venezuela. He stated that the United States would continue seizing vessels as part of this policy.

In a post on social

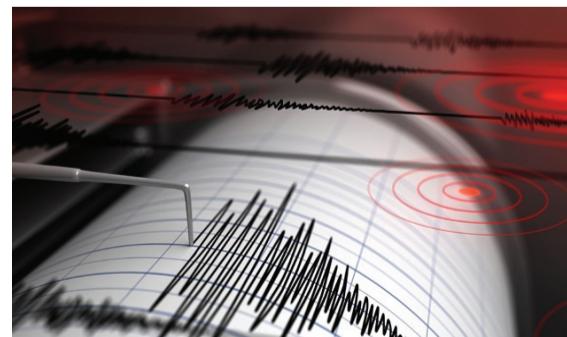
media, Trump said the blockade was intended to pressure Venezuela to return oil and other assets that he claims were taken from the United States.

The Venezuelan government strongly rejected the announcement, calling it a "reckless and serious threat" that violates international law, free trade principles, and freedom of navigation. In a statement, Venezuelan authorities accused the United States of attempting to seize resources that belong to Venezuela.

5.5-magnitude quake hits off Japan's Aomori Prefecture

Tokyo: An earthquake with a preliminary magnitude of 5.5 struck off Aomori Prefecture in northern Japan on Sunday, the country's weather agency said.

The tremor occurred at 10:29 a.m. local time off Aomori's Pacific coast at a depth of 50 km, measuring 4 on Japan's seismic scale of 7,



said the Japan Meteorological Agency (JMA).

The quake's epicenter

was located at a latitude of 40.7 degrees north and a longitude of 142.3

degrees east.

No tsunami advisory was issued.

Although a week-long alert regarding the increased risk of another strong earthquake was lifted on Monday after a 7.5-magnitude tremor struck northern and northeastern Japan on Dec. 8, JMA officials urged people to remain cautious.

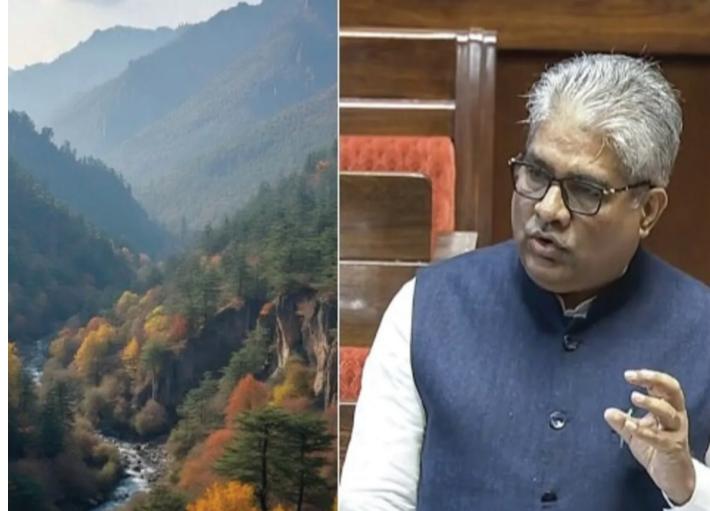
NOTICE:

Times of Pedia does not guarantee, directly or indirectly, the quality or efficacy of any product or services described in the advertisements or other material which is commercial in nature in this Newspaper. Furthermore, Times of Pedia assumes no responsibility for the consequences attributable to inaccuracies or errors in the printing of any published material from the news agencies or articles contributed by readers. It is not necessary to agree with the views published in this Newspaper. All disputes to be settled in Delhi Courts only.

अरावली को लेकर फैलाई जा रही है गलत जानकारी: केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव

नई दिल्ली: अरावली पर्वत शृंखला को लेकर सोशल मीडिया पर चल रही चर्चाओं और कथित अफवाहों के बीच केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि अरावली को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत व्याख्या की जा रही है और इससे भ्रम फैलाया जा रहा है।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को विस्तार से पढ़ा है। अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा है कि दिल्ली, गुजरात और राजस्थान में फैली अरावली पर्वत शृंखला का वैज्ञानिक तरीके से संरक्षण किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने हमेशा अरावली को हरा-भरा और संरक्षित रखने पर जोर दिया है।



भूपेंद्र यादव ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पैरा फ्ट में यह स्पष्ट किया गया है कि अत्यंत आवश्यक परिस्थितियों को छोड़कर कोई नया खनन पट्टा जारी नहीं किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि अदालत ने केवल खनन से जुड़े मामलों की जांच के लिए एक तकनीकी समिति के गठन का निर्देश दिया है।

मीटर ऊंचाई को लेकर चल रहे विवाद पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह दावा गलत है कि संरक्षण का नियम पहाड़ी की चोटी से लागू होता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि संरक्षण का आधार पहाड़ी की नींव से माना जाता है, भले ही वह जमीन के नीचे से शुरू हो। उन्होंने दोहराया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में किसी भी प्रकार के खनन की अनुमति नहीं है।

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि अरावली पर्वत शृंखला दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात के कई जिलों में फैली हुई है। इसमें बन्यजीव अभयारण्य और चार बाघ अभयारण्य शामिल हैं, जो इसके पारिस्थितिक महत्व को दर्शते हैं। उन्होंने कहा कि अरावली से जुड़ा कानूनी मामलों सुप्रीम कोर्ट में 1995 से लंबित है और सरकार अरावली में खनन के खिलाफ सख्त नियमों का समर्थन करती रही है।

इस बीच, इंडियन फॉरेस्ट सर्वे ने चेतावनी दी है कि अरावली की करीब पहाड़ियों में हो रही खनन गतिविधियां इसके क्षण का बड़ा कारण बन रही हैं। वहाँ, सेंट्रल एर्पोवर्ड कमेटी (CEC) ने भी इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप को जरूरी बताया है।

यूपी पंचायत चुनाव के लिए योगी सरकार का बड़ा कदम

अनुपूरक बजट में 200 करोड़ रुपये का प्रावधान

लखनऊ: अगले वर्ष होने वाले उत्तर प्रदेश पंचायत चुनावों को लेकर योगी सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सोमवार को विधानसभा में पेश किए गए अनुपूरक बजट में पंचायत चुनावों की तैयारियों के लिए करोड़ रुपये का प्रावधान का प्रस्ताव रखा गया है।

सरकार का कहना है कि इस राशि का उपयोग पंचायत चुनावों को शांतिपूर्ण, पारदर्शी और सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए किया जाएगा। इस निर्णय को ग्रामीण लोकतंत्र को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।

पंचायती राज विभाग से जुड़े इस प्रस्ताव के तहत त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों और उनसे संबंधित प्रशासनिक व्यवस्थाओं के लिए वित्तीय प्रावधान किया गया है। इसके अलावा, उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के कार्यालय भवन के निर्माण के लिए छ.५ करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि का भी प्रस्ताव रखा गया है।



पर विशेष जोर दे रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर पंचायत स्तर पर बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की योजना बनाई गई है।

इसके तहत प्रदेश के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रों में पंचायत उत्सव भवन या बारात घर के निर्माण के लिए प्रतीकात्मक रूप से एक लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। आवश्यक धनराशि बचत मद से वहन की जाएगी। वहाँ, जिला पंचायत शाहजहांपुर में भवन निर्माण के लिए एक करोड़ रुपये का प्रस्ताव भी रखा गया है जो सरकार का मानना है कि इन प्रावधानों से पंचायतों की प्रशासनिक क्षमता में वृद्धि होगी, ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक गतिविधियों को स्थान मिलेगा और लोकतांत्रिक प्रक्रिया और अधिक सुदृढ़ होगी। अनुपूरक बजट से ग्रामीण विकास को नई गति मिलने की उम्मीद है।

गैंगस्टर एक्ट में चयनात्मक कार्बाई से कमज़ोर हो रहा कानून का राज़: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एवं असामाजिक क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम के तहत जांच और अभियोजन प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा है कि चयनात्मक जांच और अभियोजन कानून के शासन के विपरीत हैं और इससे शासन व्यवस्था पर जनता का भरोसा कमज़ोर होता है।

न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर ने यह टिप्पणी गाजियाबाद के नंदग्राम थाने में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के एक मामले में प्राथमिकी रद्द करने की मांग पर सुनवाई के दौरान की। याचिकार्ता ने आरोप लगाया था कि गैंगस्टर एक्ट के तहत आवश्यक वैधानिक प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया और डीएम-एसएसपी की संयुक्त बैठक में आवश्यक संतोष दर्ज किए गये हैं।

कोर्ट ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था इस सिद्धांत पर आधारित है कि सभी नागरिक कानून के समक्ष समान हैं। प्रशासनिक अधिकारियों को यह समझना चाहिए कि उनके निर्णय न्याय प्रणाली की दिशा तय करते हैं और इतिहास उन्हें दर्ज भी करता है।

हाईकोर्ट ने गृह विभाग को आगाह करते हुए कहा कि चयनात्मक जांच और अभियोजन कानून के राज को कमज़ोर करते हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि संगठित और प्रभावशाली अपराधी अक्सर जमानत की शर्तों का उल्लंघन करते हैं, लेकिन अभियोजन तंत्र उन्हें प्रभावी ढांग से चुनौती देने में विफल रहता है। कोर्ट ने यह भी नोट किया कि जिन जिलों में पुलिस कमिशनरेट

जन सुनवाई में सख्त दिखे डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, लापरवाही पर राजस्व कर्मचारी निलंबित

मुजफ्फरपुर: उपमुख्यमंत्री सह भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने सोमवार को मुजफ्फरपुर में जन सुनवाई के दौरान जमीन से जुड़े मामलों में लापरवाही पर कड़ा रुख अपनाया। जन सुनवाई में बड़ी संख्या में लोग भूमि विवाद और राजस्व संबंधी शिकायतों लेकर पहुंचे।

शिकायतों की समीक्षा के दौरान मुशाहरी अंचल के सतपुरा में पदस्थ राजस्व कर्मचारी राकेश कुमार की गंभीर लापरवाही सामने आने पर उपमुख्यमंत्री ने तत्काल जिले से बाहर स्थानांतरण का

निर्देश दिया।

डिप्टी सीएम ने जिले में वर्षों से चली आ रही भूमि मामलों की अव्यवस्था, भ्रष्टाचार और अधिकारियों की लापरवाही पर नाराजगी जताई। उन्होंने कई अंचलाधिकारियों को फटकार लगाई और एक अंचलाधिकारी पर सरकारी जमीन बेचने के आरोप की जांच के आदेश दिए।

विजय सिन्हा ने कहा कि यदि सरकारी जमीन में गलत तरीके से दाखिल-खारिज, परिमार्जन या किसी भी तरह की हेराफेरी पाई गई तो कार्रवाई के बावजूद बर्खास्तगी तक सीमित नहीं रहेगी। जरूरत न पड़े।

गोवा नाइट्सलैब अग्निकांड लुथरा ब्रदर्स की पुलिस हिरासत बढ़ाई

नई दिल्ली: गोवा के 'बर्चबाय रेमियो लेन' नाइट्सलैब में हुए भीषण अग्निकांड मामले में अदालत ने क्लब के मालिक सौरभ और गौरव लुथरा की पुलिस हिरासत पांच दिन के लिए बढ़ा दी है। इस हादसे में छह लोगों की मौत हुई थी।

सुनवाई के दौरान अदालत ने जांच की प्रगति को देखते हुए यह आदेश दिया। पीड़ित परिवारों के वकील ने बताया कि हिरासत बढ़ाने का उद्देश्य घटना से जुड़े सभी पहलुओं की गहन जांच सुनिश्चित करना है। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि क्लब में सुरक्षा मानकों का पालन क्यों नहीं किया गया और आग लगने के समय आपात प्रबंधन की स्थिति क्या थी।

बताया गया है कि दिसंबर को हुए हादसे के बाद लुथरा ब्रदर्स थाईलैंड भाग गए थे, जिन्हें क्लब



दिसंबर को भारत वापस लाया गया। इसके बाद से वे पुलिस हिरासत में हैं। इस मामले में क्लब के एक अन्य मालिक अजय गुप्ता को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। पुलिस ने उनकी हिरासत बढ़ाने की मांग नहीं की थी, लेकिन जांच जारी रखेगी।

अंजुना पुलिस ने लुथरा ब्रदर्स के खिलाफ गैर इरादतन हत्या सहित अन्य गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया है। अब तक कुल आठ आरोपियों को गिरफ्तार

किया जा चुका है। इसके अलावा, ब्रिटिश नागरिक सुरिंदर कुमार खोसला के खिलाफ भी कार्रवाई तेज कर दी गई है, जो घटना के बाद यूनाइटेड किंगडम फरार हो गया था। उसके खिलाफ क्लू कॉर्नर नोटिस जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने तक किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा और हादसे के लिए जिम्मेदार सभी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

दिल्ली: 'नो PUC, नो फ्यूल' नियम लागू, 4 दिनों में 10,000 वाहन फेल

नई दिल्ली: दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए लागू किए गए 'नो PUC, नो फ्यूल' नियम के तहत बीते चार दिनों में लगभग 4,000 वाहन अनिवार्य एमिशन टेस्ट में फेल हो गए हैं।

पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने नियमों का उल्लंघन करने वाली फैक्ट्रियों और कार्यालयों को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अब बिना नोटिस के सीधे कार्रवाई की जाएगी, प्रदूषण फैलाने वाली कंपनियों को सील किया जाएगा और वर्क-फ्रॉम-होम नियमों का पालन न करने वाले ऑफिसों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा।

सिरसा ने बताया कि दिसंबर तक नए PUC सर्टिफिकेट जारी किए गए। डिल्ली कमिशनर और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC) अवैध



फैक्ट्रियों को बंद करने के लिए अभियान चला रहे हैं। मंत्री ने प्राइवेट कंपनियों को फीसदी स्टाफ क्षमता और वर्क-फ्रॉम-होम नियमों का पालन करने की कड़ी हिदायत दी।



इसके अलावा, पूरे शहर में सड़कों की धुलाई और बायोमाइनिंग से कचरा निस्तारण किया जा रहा है। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी (DD) और राजस्व विभाग के सहयोग से जल निकायों को पुनर्जीवित करने का प्रयास भी किया जा रहा है। लक्ष्य है कि पिछले कुछ वर्षों में गायब हुए कम से कम फीसदी जल निकायों को बहाल किया जाए।

दिल्ली में 120 किमी/घंटा रफ्तार से दौड़ी AUDI, तीन कारों से टकरा कर ट्रक में घुसी

नई दिल्ली। ओखला फेज-एक में सोमवार को बड़ा हादसा होते-होते बचा। एक इलेक्ट्रिक ऑडी कार अनियंत्रित होकर सर्विस लेन के किनारे खड़ी तीन गाड़ियों को टक्कर मारते हुए कंटेनर ट्रक के पिछले हिस्से में जा घुसी।

घटना में ऑडी कार का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। गनीमत रही कि एयरबैग खुलने से चालक सुरक्षित बच गया। उसे मामूली चोट आई, जिसे एक्स ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है।

दक्षिण पूर्वी जिला पुलिस उपायुक्त हेमंत तिवारी ने

बताया कि दोपहर पुलिस को

ए, ओखला फेज-एक के सामने सर्विस रोड पर कई गाड़ियों की टक्कर को लेकर पीसीआर कॉल आई। टीम मौके पर पहुंची तो पता चला कि ऑडी क्यू-आठ ई-ट्रॉन अनियंत्रित हो गई थी।

उसने पहले तीन खड़ी कारों को टक्कर मारी। फिर आगे एक खड़े ट्रक के पिछले हिस्से में टक्करने के बाद रुकी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। दुर्घटना में आडी कार चालक को हल्की चोट आयी है, जिसे एक्स ट्रॉमा

बाहर निकले तो देखा कि एक कार के भीतर या सर्विस रोड पर उस समय कोई नहीं था, ऐसे में बड़ा हादसा टल गया। पुलिस ने गाड़ी को अपने कब्जे में ले लिया और क्रेन के माध्यम से खींचकर ओखला औद्योगिक क्षेत्र थाना ले गई है।

एक अन्य प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि अनुमान के अनुसार कार की रफ्तार क्यू किलोमीटर प्रतिघंटे से ऊपर रही होगी। सर्विस लेन पर इतनी तेज रफ्तार गाड़ी को चलाने की जरूरत क्या थी। गनीमत रही कि उस समय सड़क पर कोई व्यक्ति नहीं चल रहा था अन्यथा यहां बड़ा हादसा हो सकता था।

कि बिल्डिंग यार्ड में फैली हुई थी, जिसमें एक बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर और दो ऊपरी फ्लोर थे।

उन्होंने कहा, 'हमने क्वाफायर टेंडर मौके पर भेजे, और (सोमवार को) सुबह आग बुझा दी गई।' उन्होंने यह भी बताया कि इस घटना में किसी के हताहत होने या घायल होने की खबर नहीं है। आग लगने का सही कारण अभी पता नहीं चल पाया है।



एरिया में हरीश चंद्र रोड के पास मौजूद एक फैक्ट्री से आग लगने की सूचना मिली। आग ने फैक्ट्री के

स्कियोरिटी गार्ड ने बताया कि इस घटना पर इमर्जेंसी वर्मा ने की। इसमें हवा की गुणवत्ता सुधारने से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए।

बैठक में आयोग की वार्षिक रिपोर्ट और ऑडिट रिपोर्ट को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही नवंबर के संशोधित ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) को भी मंजूरी किया गया, जिसे सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार बदला गया है।

आयोग ने बताया कि प्रदूषण के अधिक स्तर पर लागू किए जाने वाले GRAP के नियमों में नीचे के सभी स्तरों के नियम अपने आप शामिल होंगे। मौजूदा सर्विसों के मौसम में GRAP के तहत की गई कार्रवाईयों की समीक्षा की गई और विजली आपूर्ति बनाए रखने, ट्रैफिक जाम करने, लोगों को जागरूक करने और सार्वजनिक परिवहन बढ़ाने जैसे कदमों पर जोर दिया गया।

बैठक में वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए बनाई गई विशेषज्ञ समिति को भी मंजूरी दी गई। इस समिति की अध्यक्षता IIT मद्रास के प्रोफेसर अशोक झुनझुनवाला करेंगे। यह समिति वाहन प्रदूषण, स्वास्थ्य पर इसके असर, साफ-सुधारे परिवहन, इलेक्ट्रिक वाहनों की तैयारी और नियमों में सुधार से जुड़े विषयों पर काम करेंगी।

आयोग ने टैक्सी एग्रीगेट्स, डिलीवरी और ई-कॉमर्स कंपनियों के लिए शून्य-उत्सर्जन वाहनों पर भी चर्चा की। तथा किया गया कि मौजूदा क्लीट में BS-VI पेट्रोल दोपहिया वाहन दिसंबर तक शामिल किए जा सकेंगे, जबकि अन्य ट्रेणिंगों में सामान्य पेट्रोल-डीजल वाहनों को वर्जनवारी खंड से शामिल करने पर

दिल्ली-NCR में प्रदूषण नियंत्रण: CAQM ने बैठक में लिए अहम फैसले

नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर और आसपास के इलाकों में वायु प्रदूषण को लेकर बैठक सोमवार को हुई। बैठक की अध्यक्षता आयोग के चेयरपर्सन राजेश वर्मा ने की। इसमें NCR में पराली जलाने की घटनाओं में करीब -4 ग्रेड प्रतिशत की कमी आई है। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश को निर्देश दिए गए कि वे में गेहूं की कटाई के समय पराली जलाने से रोकने के लिए राज्य स्तर पर कार्ययोजनाएं तैयार करें।

इसके अलावा औद्योगिक इकाइयों पर की गई कार्रवाई, बंद और फिर से शुरू की गई फैक्ट्रियों तथा कानूनी मामलों की स्थिति की भी समीक्षा की गई। निर्माण और तोड़फोड़ से निकलने वाले कचरे पर कार्ययोजनाएं तैयार करें। इसके साथ ही नवंबर वाले GRAP के नियमों में नीचे के सभी स्तरों के नियम अपने आप शामिल होंगे। मौजूदा सर्विसों के मौसम में GRAP के तहत की गई कार्रवाईयों की समीक्षा की गई और विजली आपूर्ति बनाए रखने, ट्रैफिक जाम करने, लोगों को जागरूक करने और सार्वजनिक परिवहन बढ़ाने जैसे कदमों पर जोर दिया गया।

बैठक में पुराने और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के मुद्रे पर भी चर्चा हुई। आयोग ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के दिसंबर के आदेश के अनुसार BS-IV और उससे नए वाहनों को फिलहाल जबरन कार्रवाई से राहत मिलेगी, जबकि BS-III और उससे पुराने अधिक प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकेगी। संबंधित एजेंसियों को इन आदेशों का सख्ती से पालन करने को कहा गया।

आयोग ने कहा कि सर्विसों के मौसम में वायु प्रदूषण पर काबू पाने के लिए सभी विभागों को मिलकर लगातार निगरानी करनी होगी और नियमों को सख्ती से लागू करने की बात कही। सभी एजेंसियों ने प्रदूषण नियंत्रण के उपायों को पूरी गंभीरता से लागू करने की बात कही।

Muslims Must Step Forward With Individual and Collective Efforts for Communal Harmony in the Country: Syed Sadatullah Husaini, President, JIH

New Delhi: Jamaat-e-Islami Hind's Communal Harmony Department organised a two-day programme titled All India Communal Harmony Coordinators' Meet, in which men and women working at the grassroots level for communal harmony from nearly 20 states across the country participated. The objective of the meeting was to understand the situation of communal harmony in different states, review the work carried out so far, and provide guidance for future efforts. Addressing the gathering, the President of Jamaat-e-Islami Hind, Syed Sadatullah Husaini, said in his keynote address that work for communal harmony is not temporary but permanent in nature. He said Islam is founded on correcting relationships among people and guiding them in the right direction. He added that the Quran places great emphasis on this, and the Prophet

All-India Communal Harmony Coordinators' Meet Held in Delhi



Muhammad (pbuh) devoted his entire life to this cause. He further said there is now a need to take this work beyond the individual level and strengthen it at the institutional level so it rests on firm foundations. The Secretary General of Jamaat-e-Islami Hind, T Arif Ali, said efforts for communal harmony are not a response to

situational pressure. He said they are a responsibility and have always been part of the policy of Jamaat-e-Islami Hind. He added that just as harmony exists in every aspect of Allah's creation, harmony among human beings is also essential. On the occasion, Swami Sarvalok Anand Ji Maharaj spoke on the importance of inter-

faith dialogue for communal harmony and urged people to understand and respect their own beliefs as well as those of others. Gyani Mangal Singh Ji spoke on the importance of building bridges among all communities and said selfless service to people is the most effective means to achieve this. Ms Shaista Rifat, National Sec-

retary of Jamaat-e-Islami Hind, spoke on the role of women in communal harmony. She said half of the world's population cannot be kept away from this effort. She urged women to come forward and play an active role, and said society and the nation must provide them with maximum opportunities in this regard. During the programme, participants exchanged views on various ideas to make the Dharamik Jan Morcha and Sadbhavana Manch more active and effective across the country. Prof Salim Engineer, Vice President of Jamaat-e-Islami Hind, advised participants to work with confidence and without discrimination. At the conclusion of the programme, participants from across the country expressed their resolve to unite all sections of society with full strength, patience, wisdom, perseverance, and courage.

Railways hikes travel fares, AC tickets to cost Rs 10 more for every 500 km

New Delhi : Indian Railways will implement a rationalised passenger fare structure from December 26, 2025, under which fares for long-distance travel will increase

marginally while short-distance, suburban, and season ticket passengers remain unaffected.

Under the revised structure, there will be no increase in fares for sub-

urban train services and monthly season tickets, Railways said. Ordinary Class passengers travelling up to 215 km will also not see any hike in ticket prices.

Despite No Stubble Burning or Firecrackers, Delhi Breathes Clean Air for Only 9 Days in Six Years

New Delhi: Even in the absence of stubble burning and firecrackers for much of the year, Delhi continues to remain a gas chamber. A startling data point underlines the severity of the crisis: over the past six years, residents of the national capital have experienced

clean air on only nine days.

A thick blanket of smog has become a familiar sight for Delhiites stepping out of their homes. This persistent haze tells a grim story of air pollution, while debates and blame games dominate social media and television studios.

SUBSCRIPTION FORM TIMES OF PEDIA

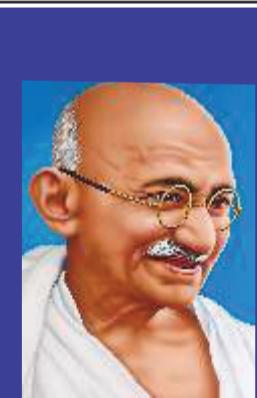
Issue	Subscription Price	Years
52	250/-	1
104	500/-	2
260	1,300/-	5
520	2,600/-	10
--	5,000/-	Life

Name :.....
Address :.....

Email:.....
Contact Phone No. for donation /life /10 yrs /5 yrs subscription
The sum of Rupees..... (Rs...../-) through cheque/DD No.....dt.....

Fill the above form neatly in capital letters and send it to us on the following address :
Times of Pedia, K-2-A-001, Abul Fazal Enclave-I, Jamia Nagar, Okhla, New Delhi-110025 or email : timesofpedia@gmail.com

Also Send us your subscription, membership, donation amount in favour of Times of Pedia, New Delhi Punjab National Bank, Nanak Pura Branch, New Delhi-110021 A/C No.1537002100017151, IFS Code : PUNB 0153700



“First, they ignore you, then they laugh at you, then they fight you and then you win.”
- Mahatma Gandhi

ADVERTISEMENT TARIFF TIMES OF PEDIA

Size/Insertion Single	B&W (Rs)	4 Colour (Rs)
Full Page (23.5 x 36.5 cm)	30,000/-	1,00,000/-
A4 (18.7 x 26.5 cm)	20,000/-	60,000/-
Half Page (Tall-11.6 x 36.5 cm)	18,000/-	50,000/-
Half Page (wide-23.5 x 18 cm)	8,000/-	50,000/-
Quarter Page (11.6 x 18 cm)	10,000/-	28,000/-
Visiting Card size (9.5 x 5.8 cm)	3,000/-	10,000/-

MECHANICAL DATA:

Language: English, Hindi and Urdu

Printing: Front and Back - 4 Colours, Inside pages - B&W

No. of Pages: 12 pages (more in future)

Price: Rs. 3/-

Print order: 25,000

Periodicity: Weekly

Material details: Positives/Format of your advertisements should reach us 10 days before printing.

Note: 50% extra for back page, 100% extra for front page

Please Add Rs. 10 for outstation cheques.

50% advance of total add cost would be highly appreciable, in case of one year continue add. Publication cost will reduce 50% of actual cost.

Bank transactions details of TIMES OF PEDIA

Send your subscriptions/memberships/donations etc.

(Cheques/DD) in favour of TIMES OF PEDIA New Delhi Punjab National Bank, Nanak Pura Branch, New Delhi-110021 A/C No.1537002100017151, IFS Code : PUNB 0153700

अफ़गानिस्तान में अधिकारिक रूप से तिब्ब ए यूनानी की शुरुआत

डॉ. ओबैदुल्लाह बेग की मेहनत रंग लाई अफ़गानिस्तान और भारत सरकार ने मेडिकल क्लिनिक में किया समझौता

नई दिल्ली। ऑल इंडिया यूनानी तिब्ब ए यूनानी की अधिकारिक रूप से शुरुआत हो गई है और अफ़गानिस्तान में तिब्ब ए यूनानी की अधिकारिक रूप से शुरुआत हो गई है। इस संबंध में ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कांग्रेस ने दोनों देशों का शुक्रिया अदा किया है। ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोफेसर मुश्ताक अहमद और सेक्रेटरी जनरल डॉ. सैयद अहमद खान ने संयुक्त रूप से खुशी का इजहार करते हुए कहा कि भारत सरकार के इस कदम से तिब्ब ए यूनानी का और विकास होगा।

डॉ. ओबैदुल्लाह बेग ने कहा कि भारत सरकार, खासकर आयुष मिनिस्टर प्रताप राव जाधव के हम आभारी हैं कि उन्होंने अफ़गानिस्तान



में तिब्ब ए यूनानी का एक नया चैप्टर शुरू किया है।

इस सिलसिले में जो डेलीगेशन अफ़गानिस्तान से मौलवी नूर जलाल

जलाली (पब्लिक हेल्थ मिनिस्टर) की लीडरशिप में दिल्ली आया उसमें पब्लिक हेल्थ मिनिस्ट्री से जुड़े अब्दुल्ला इसराइली, फजल रबी

करीमी, सैयद मुहम्मद इब्राहिम खेल, सैयद हारून आजाद, खालिद अहमद मुहम्मद अका, सफूतुल्लाह देवबंदी और मुजीब-उर-रहमान आफताब शामिल थे हम उनके भी शुक्रगुजार हैं क्योंकि उनकी दिलचस्पी की वजह से ही यह बड़ी कामयाबी मिली दोनों देशों के बीच हुए समझौते से अफ़गानिस्तान में यूनानी रिसर्च शुरू होगी और अफ़गान स्टूडेंट्स को भारत में फ्री बीयुएमएस (BUMS) की शिक्षा दी जाएगी।

जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। डॉ. ओबैदुल्लाह बेग ने आगे कहा कि यह समझौता तिब्ब ए यूनानी को पसंद करने वालों के लिए बहुत अच्छा है और इससे तिब्ब ए यूनानी और मजबूत होगी और इसे दुपरे देशों में भी बढ़ावा मिलेगा।

खोखली हड्डियों को मज़बूत बनाने के लिए खाएं अंजीर, दर्द और कमज़ोरी भागेगी दूर

नई दिल्ली। कव्या आपकी हड्डियों में भी आए दिन दर्द रहता है और आपको चलने-फिरने में दिक्कत महसूस होती है। अगर हाँ तो फिर आपको आज से ही अपने खानापान में बदलाव कर लेना चाहिए।

अंजीर न केवल खाने में स्वादिष्ट होता है बल्कि यह औषधीय गुणों से भी भरपूर होता है जो सेहत और खासकर आपकी हड्डियों के लिए भी बेहद फायदेमंद है। यह शरीर को पोषण प्रदान करता है और कई रोगों में राहत देने में कागर है।

अंजीर में मौजूद कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस और विटामिन-के हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करते हैं। खासकर उन



लोगों के लिए जो पहले हड्डियों की कमज़ोरी से जूझ रहे हैं।

इसके अलावा अंजीर में कई एंटी-ऑप्सिंडेंट्स और फाइबर भी होता है जो पाचन तंत्र को दुरुस्त रखकर हड्डियों को स्वस्थ रखने में योगदान

देता है। अगर आप अंजीर को संतुलित डाइट और फिजिकल एक्टिविटी के साथ अपनी लाइफस्टाइल में शामिल करेंगे तो आपको हड्डियों की मजबूती के साथ कई और स्वास्थ्य लाभ भी मिलेंगे।

अंजीर को आप कैसे भी खा सकते हैं। आप सूखे अंजीर इसे रोजाना स्नैक के तौर पर खा सकते हैं या फिर इन्हें ऑटमील, दही या स्मूदी में मिलाकर भी खा सकते हैं। हड्डियों की हेल्थ के लिए आप इन्हें अगर दूध में भिगोकर खाते हैं तो ज्यादा बेहतर है। हालांकि एक बात ध्यान रखें कि हड्डियों की मजबूती के लिए आपको विटामिन्स, मिनरल्स और बाकी पोषक तत्वों से भरपूर भोजन करना चाहिए और साथ ही रोजाना कोई ना कोई एक्सरसाइज भी करनी चाहिए। ये सभी चीजें मिलाकर आपकी हड्डियों को मजबूत बनाएंगी और उन्हें बुढ़ापे तक मजबूत भी रखेंगी।

करने में भी मदद करता है, जिससे दिल की सेहत बेहतर रहती है। रोज पर से ब्रेंग अदरक चाय या खाने में डालकर लिया जा सकता है।

सब्जियां सेहत के लिए जरूरी हैं, लेकिन जब इन्हें पकाकर खाया जाता है तो शरीर इन्हें और बेहतर तरीके से पचा पाता है। गाजर, पालक, ब्रोकली और टमाटर जैसी सब्जियों को पकाने से उनके पोषक तत्व आसानी से शरीर में अव्यावृत हो जाते हैं।

पकी हुई सब्जियों से विटामिन A, C, K, आयरन, पोटैशियम और फाइबर अच्छी मात्रा में मिलता है। ये दिल को हेल्दी रखने, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने और पाचन मुश्धाने में मदद करता है। रोजाना अदरक खाने से पेट से जुड़ी समस्याएं जैसे गैस, उलटी, मतली और अपच में राहत मिलती है।

अदरक मसल्स और जोड़ों के दर्द को भी कम कर सकता है, खासकर गर्भिया के मरीजों के लिए ये फायदेमंद माना जाता है। इसके साथ ही ये बैंड कोलेस्ट्रॉल को डाइटरियों और ग्रीन फ्रैश को लिए भी हल्की होती हैं। ऑटमील एक ऐसा अनाज है, जो रोज खाने से शरीर को

कई फायदे मिलते हैं। इसमें मौजूद बीटा-ग्लूकन नाम का फाइबर बैंड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और दिल की बीमारियों का खतरा घटाता है। ऑटमील धीरे-धीरे पचता है, जिससे ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है।

यही वजह है कि यह डायबिटीज के मरीजों और वजन कम करने वालों के लिए अच्छा माना जाता है। ऑटमील पेट को लंबे समय तक भरा रखता है, जिससे बार-बार भूख नहीं लगती। इसके अलावा इसमें मौजूद एंटीऑक्सिडेंट्स सूजन कम करने और ब्लड वेसल्स को हेल्दी रखने में मदद करते हैं। सेहत के लिए इंसुलेट ओटोस की बजाय रोल्ड या स्टील-कट ऑटोस बेहतर माने जाते हैं।

उबला हुआ चावल शरीर को तुरंत और लंबे समय तक नर्जिस देने का काम करता है। खासकर पारबॉल्ड चावल में फाइबर और प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए फायदेमंद है।

खेल समाचार

वैभव सूर्यवंशी के शौर्य पर काले बादल! जल्दी शोहरत, IPL में बरसता पैसा बन सकते हैं जंजाल



U-19 एशिया कप 2025 के फाइनल में भारत की करारी हार ने यह साफ कर दिया कि प्रतिभा और रिकॉर्ड अपने आप बड़े मुकाबले नहीं जितते। वैभव सूर्यवंशी की विस्कोटक क्षमता के बावजूद, जल्दबाजी, दबाव और IPL में मिली जल्दी शोहरत उनके करियर के लिए चुनावी बन सकती है।

दुबई में खेला गया एसीसी मेन्स अंडर-19- एशिया कप 2025 का फाइनल भारतीय क्रिकेट के लिए आईना लेकर आया... और उस आईने में दिखी तस्वीर आरामदेह कर्तृत नहीं थी।

पाकिस्तान के खिलाफ रनों की करारी हार ने बेरहमी से यह सच उजागर कर दिया कि प्रतिभा, रिकॉर्ड और गौरवशाली इतिहास बड़े मुकाबले नहीं जितते, अगर तैयारी अधूरी और मानसिकता कच्ची हो।

यह परायज किसी एक ओवर, एक कैच या एक गलत शॉट का नतीजा नहीं थी। यह रणनीति की विफलता, दबाव में टूटती बल्लेबाजी और बड़े मंच पर लिए गए गलत फैसलों का सामूहिक परिणाम थी।

... और इसी मलबे के बीच एक नाम ऐसा था, जिस पर उम्मीदों का सारा बोझ भी था, बहस की सारी आग भी और भारतीय क्रिकेट के भविष्य की दिशा तय करने का दबाव भी.... वह नाम है- वैभव सूर्यवंशी।

भारत अंडर-19- एशिया कप के इतिहास की सबसे सफल टीम रही हैं। शुरू हुए इस टूर्नामेंट में भारत ने रिकॉर्ड न बाल रखा है। इस दौरान टीम 2025 में पाकिस्तान के साथ संयुक्त विजेता भी रही। ऐसे गौरवशाली इतिहास के साथ फाइनल खेलना सिर्फ समान नहीं, बल्कि दबाव भी लाता है। दुबई में भारतीय टीम उस दबाव से निपट नहीं सकी।

वैभव सूर्यवंशी इस टीम का चेहरा थे। यूएई के खिलाफ क्वार्टर रनों की विस्कोटक पारी ने उन्हें टूर्नामेंट का पोस्टर बॉय बना दिया। उस पारी में उनकी नैसर्गिक प्लेयर, विस्कोटक ताकत और आत्मविश्वास सापेक्षता था।

...लेकिन उसी पारी ने उनके खेल को एक तय फ्रेम में भी कैद कर दिया। हाई-इंस्टेंट, हर गेंद पर हमला। इसके बाद पूरे टूर्नामेंट में वह सिर्फ एक बार के अंकड़े तक पहुंचे, वह भी मलेशिया जैसे कमज़ोर विपक्ष के खिलाफ। फाइनल में पाकिस्तान के सामने टॉप ऑर्डर पर उनका जल्दी आउट होना भारत के अहम कारणों में से एक रहा।

फाइनल ने यह भी दिखा दिया कि पेशेवर क्रिकेट सिर्फ ताकत और आक्रामकता का खेल नहीं है। परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालना, स्ट्राइक रोटेशन करना और सही समय पर फैसले लेना उन्हाँ से जूझती है। पाकिस्तान ने वैभव के खिलाफ यही किया- क्वालिटी स्पिन, हार्ड लैंथ और सिंगल्स पर सख्त नियंत्रण। वैभव उस जाल को पढ़ नहीं सके।

फाइनल में पाकिस्तान के अली रजा के साथ हुआ गर्मगर्म वाक्या और विरोधी खिलाड़ी की ओर किया गया 'जूते वाला इशारा' व्यापक रूप से भावनात्मक अपरिक्वता के संकेत के तौर पर देखा गया। कच्ची प्रतिभा मैच जीत सकती है, लेकिन टेम्परामेंट ही चैपियन बनाता है।

फाइनल में पाकिस्तान के अली रजा के साथ हुआ गर्मगर्म वाक्या और विरोधी खिलाड़ी की ओर किया गया 'जूते वाला इशारा' व्यापक रूप से भावनात्मक अपरिक्वता के संकेत के तौर पर देख

ذہنی دھندر: دماغ کی بغاوت یا جدید زندگی کی المیاتی پیداوار؟

محنت ثابت ہوئی۔ اس نے اسے رکنے اور سوچنے پر مجبور کیا۔ اس نے پہلی بار اپنے جسم کے بھیج گئے نتیجات میں نہیں تسلیم کیا۔ اس کا حل کسی جادوی گولی میں نہیں تھا، بلکہ اپنی زندگی کے طریقے کو بدلتے میں تھا۔ اس نے صحن اچھے کر فون چیک کرنے کی بجائے اس منصب اپنی سانسونو پر تو جرم کروز کرنا شروع کی۔ اس نے ملٹی نا سلکنگ کو خیر بارا کھا اور ایک وقت میں یک کام کرنے کے قدمیں اصول کو دوبارہ اپنایا۔ اس نے رات کو سونے سے ایک گھنٹے پہلے بیاننا لو یہی سے طلتوڑ کر کتاب پڑھنے کی عادت ڈالی۔ اس نے اپنی زیر سے انزیح ڈر فلی ڈر اس ہٹا کر پانی کی بوقت اور پھل رکھ لیے۔ یہ تبدیلیاں معمولی تھیں، لیکن ان کے اثرات گھرے تھے۔ میمونوں کی مسلسل کوشش کے بعد، اس نے محسوس کیا اس کے ذہن کا اندر وہی موسم بدیں رہا ہے۔ دھنچھڑت، ریتی، اور سوچ کا نیا آسمان دوبارہ نظر آنے لگا تھا۔ اسے احساس ہوا کہ ذہنی وضاحت کوئی ایسی چیز نہیں ہے حاصل کیا جاتا ہے، بلکہ یہ مماری فطیحی حالت ہے جسے ہم نے جدید زندگی کے



شور میں ہو گیا ہے۔ آخر میں، بیرین فاک کا بڑھتا ہوا پھیلاوہ ہم سے ایک بیانی سوال پوچھتا ہے: ہم کیسی نیا تعمیر کر رہے ہیں؟ ایک دنیا جو انسانی ذہن کی یادیاتی تحقیقت کا اخترام کرتی ہے، یا ایک ایسی دنیا جو سے ایک میں سمجھ کر اس کی آخری حد تک پہنچ لیتا چاہتی ہے؟ اس وضد سے نکلے کا راستہ مزید تیز رفتار پیش یا بایوپیکنگ بھیں نہیں، بلکہ ست ہونے، تدریت سے جڑنے، حقیقی انسانی تعلقات استوار کرنے اور اپنے جسم کی دناتھی کو سنبھلے میں ہے۔ یہ ہمارے لیے ایک موقع ہے کہ ہمینکا لوگی کو اپنے آقا کے طور پر نہیں، بلکہ اپنے انسانی مقاصد کے حصول کے لیے ایک آئے کے طور پر استعمال کریں۔ علی کی طرح، میں بھی اپنی زندگیوں میں اس لمحے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے جب ہمارا دماغ کام کرنا چھوڑ دے، بلکہ آج ہی سے ان خاموش سکندر پر توجہ دئی ہوگی جو ہمیں ایک یادہ متوازن اور حقیقی زندگی کی طرف بلا رہے ہیں۔ شاید تب ہی ہم بحیثیت مجموعی اس ذہنی وضد سے کوک کر ایک روشن اور واضح مستقبل کی طرف دیکھ پایں گے۔

مرکز ہماری آئینیں ہیں۔ علی، اپنی طویل کام کی شفشوں کے دوران، کافی، ایزجی ڈرکس اور پر دیسینڈ اسٹیکس کو اپنا یہ دن سمجھتا تھا۔ اسے یہ معلوم نہ تھا کہ اس کا یہ "اینڈھن" دراصل اس کے جسم کے اندر ہی ایک آگ بھکر رہا تھا۔ حالیہ حقیقت نے "گٹ-برین ایکس" (Gut-Brain Axis) کے ذریعے ثابت کیا ہے کہ یہ غذا یا آئنوس میں جو سوڑک پیدا کرتی ہیں، وہ اعصابی راستوں کے ذریعے براہ راست دماغ تک پہنچ کر "نیوروا-ٹلیمینشن" (اعصابی سوڑک) کا باباعد بیٹھتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ لائگ کو ووڈ-19 کے لاکھوں مریض، وائرس کے جسم سے نکل جانے کے میں بیوں بعد بھی شدید برین فیاگ کا ڈکھار رہے۔ کو ووڈ نے دراصل اس خاموش و بوا کو عالمی مظہر ناتے پر نہیں کر دیا اور اس حقیقت کو تسلیم کروایا کہ جسمانی سوڑک براہ راست ہماری سوچ کی صلاحیت پر حملہ آرہو ہے۔ ہمارا جسم ایک پیچیدہ ماحولیاتی نظام ہے، اور جب ہم ناقص خوارک، ورزش کی کمی اور رانی دباؤ کے ذریعے اس کا توازن لگاتے ہیں، تو دماغ اس کی قیمت ادا کرتا ہے۔ علی کے لئے وہ منہج ایک اللہ نہیں، بلکہ ایک

Andrew Huberman (اندرو ہبمن) پریور یو چیور میں ایک ایڈیٹر ہے۔ وہ اپنے کاریکچر کے طبق، اسکرولنگ ہمارے دماغ کے ڈیپی مین سٹم کو اپنائی جیک کر لیتے ہیں۔ ہر لینک، کوئٹہ یا انی پوسٹ ڈیپی مین کا ایک چھوٹا سا جھنکا دیتی ہے، جو ہمیں بار بار پسون کی طرف سمجھتا ہے۔ اس مسئلہ خلاشہ کا تجھے یہ ہے کہ ہمارا دماغ طوبی مدقی، گہری تو جو کی صلاحیت کھو چکتی ہے اور جھوٹی چھوٹی، فوری تسلیکن کا عادی ہو جاتا ہے۔ علی کو یہ احساس نہیں تھا کہ رات کو بستر پر لیت کر ۱۰۰ صرف پانچ منٹ کے لیے فون دیکھنا دراصل اس کے دماغ کو اگلے دن کی ناکامی کے لیے تیار کر رہا تھا۔ یہ صرف نیلی روشنی کا مسئلہ نہیں، یہ دماغ کو ایک منسلق اضطراب اور بے چینی کی حالت میں بنتا رکھنے کا عمل ہے جو ذہنی وضاحت کو ناکام بنادیتا ہے۔ کیا یہ ترقی ہے یا ذہنی اخبطاط، کرتاری کی سب سے زیادہ معلومات تک رسائی رکھنے والی اس لائن اپنی تو جو کچھ دیکھنے سے زیادہ مرکوز رکھنے کی صلاحیت کھو رہی ہے؟ یہ ذہنی وہند صرف ہمارے سرو میں ہی نہیں، جس کا بلکہ ہمارے پورے وہ دنیا میں ہر اس رہتی ہے، جس کا

میکن نیدرگارڈ (Maiken Nedergaard) نے 2012 میں ۱۰ گلیمفیٹک سسٹم (Glymphatic System) کو دریافت کر کے ثابت کیا کہ ہر نیند کے دوران دماغ کو دھوکران زہر لیلے پر ڈھینز (مثلاً بیٹا-امیلیوامید) کو صاف کرتا ہے جوں بھر کے ڈھنی کاموں کے نتیجے میں جمع ہوتے ہیں۔ جب ہم اپنی نیند پوری نہیں کرتے تو یہ کچھا ہمارے نیوراٹز کے ریزیان جمع ہوتا رہتا ہے، جو اگلے دن سوچنے کی رفتار کو مست کر دیتا ہے، تو جو کو منشتر کرتا ہے اور یادداشت کو مکروہ بناتا ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کسی شہر کا مقابلی کا نظام رات کو کام کرنا چھوڑ دے اور بالکل جمع ہرگی اور ٹوڑے کے ڈھیر سے بھری ہو۔ اگر نیند کی اس سلسلہ کا ایک بہلو ہے تو ڈیجیٹل دور کا معلومات کا یلیاب اس کا دوسرا، اور شاید زیادہ خطرناک، بہلو ہے۔ ہم ایک "تو جو کی معیشت" (Attention Economy) میں جی رہے ہیں، جوں ہماری توجیہ یک فیٹی ہے ہے جسے ہر قیمت پر خیریا اور بیچا جاتا ہے۔ اسٹینفورد یونیورسٹی کے نیوروسائنسٹ ڈاکٹر

اسما، جبین فلک

علی کو وہ لمحہ اپنی روح پر ایک نقش کی طرح یاد ہے۔ وہ اپنے کیہر کی بلندترین عمارت کے انفراس روم میں تھا، جہاں ہر نظر ایک عدسے کی طرح اس پر مرکوز ہی۔ اچانک، اس کے ذہن میں کچھ ٹوٹ گیا۔ جیسے کسی نے شعور کی ہارڈ ڈرائیور پر فارمیٹ کا ٹھنڈا ڈبایا ہو۔ وہ الفاظ جہاں کی زبان پر تھے، بھاپ بن کر اڑ گئے۔ وہ اعداد و شمار جن پر اس کی مایلی کا انحصار تھا، ایک بے معنی گورکھ دھنے میں تبدیل ہو گئے۔ اسے یوں لگا جیسے اس کے خیالات کا کہاں بھج دیکھا ہے اور وہ ایک خالی، گوچتی ہوئی خاموشی میں قید ہے۔ کمرے کی روشنیاں ناقابل برداشت حد تک تیر محسوس ہونے لگیں اور کافوں میں ایک لیکلی سی سسناہٹ نے ہر دوسری آواز کو دبایا۔ یہ حصہ یادداشت کی تاکاہی نہیں تھی؛ یہ اس کے وجود کا اپنے ہی دماغ سے رابط متعلق ہو جانے کا ایک دھشت ناک تجھر تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جس علی نے پہلی بار ”برین فاگ“ کو ایک طبی اصطلاح کے طور پر نہیں، بلکہ اپنی ذات کے انہدام کی ایک زندہ حقیقت کے طور پر محسوس کیا۔ علی کی کہانی حصہ ایک فردی کی داستان نہیں، بلکہ یہ جدید دور کے انسان کا اجتماعی الیہ ہے۔ ہم ایک ایسی تہذیب میں جی رہے ہیں جو رفار، پہنچا اور یہ آن لائن رہنے کے جنون میں بنتا ہے۔ اس تناظر میں، وہنی دھنہ یا برین فاگ (Brain Fog) کوئی خرابی یا پاری کی نہیں، بلکہ یہ ہمارے حیاتیاتی وجود کی طرف سے ایک بخاوت ہے۔ یہ ہمارے جسم اور دماغ کا اس غیر نظری رفتار کے خلاف ایک انتباہی نظام ہے، ایک چیز ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ ہم اپنی مطہری حدود سے بہت تجاوز کر چکے ہیں۔ اس ذہنی بخاوت کی جڑیں ہمارے سونے کے کمروں تک پہنچی ہوئی ہیں۔ کار پوریٹ کلچر اور مسابقت کی دوڑ نے ہمیں یہ سکھایا کہ کہنا ایک عیاشی ہے، جسے کم کر کے پہنچا اور یہ بڑھائی جاسکتی ہے۔ علی کی کہانی اس کی ایک تلخ مثال ہے، جو اکثر رات لگنے تک ای میلاد اور پر نیشنیٹ میں ال جھارہتا، اور بچا کھچا وقت اسکریں پر کردار دیتا۔ ہم یہ سمجھنے سے قاصر رہے ہیں کہ نیندہ دماغ کے لیے حصہ آرام نہیں، بلکہ ایک غفال صفائی کا عمل ہے۔ معروف نیوروسائنسٹ

ایجنبی کو بتایا کہ جنگ کے بعد سائب وزیر اعظم کے لیے خاص طور پر ان کے حامیوں کی طرف سے گولڈمنیر کے ساتھ نفرت اور ان کے حامیوں کے ساتھ نفرت میں نورت سے نفرت ایک سخت نا انسانی تھی یعنی ان کا عورت ہوتا اگرچہ انہوں نے ریاست کے لئے اپنی بیوی اور اہم کردار ادا کیا تھا لیکن کہا جاتا ہے کہ وہ اسرائیل ریاست کے قیام کے ودرسے پہلو پر غور کرنے میں ناکام اور نا اہل حسیں اور اسی لیے فلسطینیوں کو وہاں سے نکلنا پڑا۔ یہ دوسرا پہلو فلسطینیوں کی وہاں موجودی تھی جس کے بارے میں انہوں نے کہا تھا فلسطینی ریاست میں ایک ازاد فلسطین کو ایسا کہتے تھا کہ فلسطین میں کوئی فلسطینی تھا جو اپنے آپ کو فلسطینی قوم سمجھتا تھا اور ہم نے آئرلینڈ یا ہر کمال دیا اور ان کا ملک جھیں لیا، وہ یہاں موجود ہیں بیٹھنے تھے۔ ان کی یہ بات اور اسرائیل کی تھیں اس بات کی علامت ہے کہ فلسطینیوں کی شناخت کو ظریف اور اذکیا گیا، مسلم امریکی طور سے عرب خاموش رہے بلکہ اسرائیل کو مددوی جو آج بھی خاص طور ہے کہ اسی طرح ہے لیکن آج ساری دنیا دیکھ رہی ہے، سمجھ رہی ہے اور مظلوم کا ساتھ دینے کے لیے کجا بھی ہے آج سو شل میڈیا یا عوام کو کچھ بتانے اور سمجھانے کے لیے بہت اہم ہے۔ گولڈمنیر کے یہ جملے اگر آج بولے گئے ہوتے تو سو شل میڈیا ایک طوفان اٹھادیں یہ میں کامیاب ہو جاتے آج سو شل میڈیا کی اہمیت سے انکار نہیں ہے اور نہ کسی جا سکتا ہے۔ لوگوں کا راوی تی میڈیا کی نسبت سو شل میڈیا پر عبار بڑھ گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں کے دوسرے میں ہے۔ یہاں کوہ کی سے کسی بھی وقت سوال کر سکتے ہیں، ثبوت مانگ سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کہ بات کرنے والا کتنا معتر اور اس کی بات میں کس قدر و زدن ہے لہذا یا بھر کے اور پاکستان کے عوام کے لیے سو شل میڈیا خصوصاً ٹویٹر ایک نئی طاقت اور ایک نیا ہتھیار ہے۔

نفرت اور محبت



بچھے دونوں گولڈا میر کے پوتے نے اسرائیل کی نیوز طور پر مضبوط نہیں بلکہ کمزور بنایا ہفت سے اسرائیلی اسی

غزالہ عزیز
لوگ جیان ہوتے ہیں کہ امریکا اور اسرائیل کے درمیان اتحاد کے قائم ہوا ہے بھی اتنا گہرا کہ امریکا اپنا امیت، اپنا فائدہ دونوں کی پروانہ کرے دنیا میں اٹھتے نفرت کے طوفان کو نظر انداز کر دے۔ آپ کا کیا خیال ہے اسرائیل کی سیاست میں درندگی قبل و غارت گری اور اس کی پشت پانی ہے دنیا کو نظر نہیں آرہی؟ سب جانتے ہیں اس بولتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ نفرت جو اسرائیل کے لیے ہے وہ امریکا کے لیے بھی موجود ہے اظہار کرتے خوف کھاتے ہیں۔

امریکا اسرائیل اتحاد کی کم از کم چچا سالہ طویل تاریخ ہے اور یہ اتحاد قائم کرنے میں سب سے زیادہ جو کردار تھا وہ اسرائیل کی سابق وزیر اعظم گولڈا میمر کھانا اگرچہ وہ اس وقت وزیر خارج تھی لیکن انہوں نے اس بات کے لیے اقوام تجده کو تیار کیا کہ اسرائیل کی آواز کو ستا جائے اور مانا جائے انہوں نے امریکا کو اس وقت یعنی 1956ء میں اسرائیل کو تھیار فروخت کرنے پر بھی راضی کیا اگرچا ان کے درمیان اس وقت اتنی قربت نہیں تھی لیکن گولڈا میمر ایک ایسی شخصیت تھیں جنہوں نے اسرائیل کو 1967ء میں چھ دن کی جنگ میں اسرائیلی کوشش نہ سکر کیا میں ایسا لیکن جنکہ جنگ میں اسرائیل کے 2700 فوجی ہلاک ہوئے تھے لہذا اس جنگ کو گولڈن میر کی ناکامی کے طور پر دیکھا گیا۔ انہوں نے جنگ کے بعد وزیر اعظم کے عہدے سے انتخابی دے دیا، وجہ اتنی بڑی تعداد میں اسرائیلی سپاہیوں کی بلاکت تھی۔ وہ بھتی ہیں کہ انہوں نے اس بات کو سمجھیہ نہیں لیا کہ مصراو شام حملہ کریں گے؛ حالانکہ انہیں اردن کے باڈشاہ کی جانب سے مطلع کیا جا پڑا تھا۔ انہوں نے اسرائیلی اٹھائیں ایجمنوں کی بات پر اعتبار تھا جنہوں نے اس کو سمجھیدہ خطرہ قرار نہیں دیا تھا مگر جب شام اور مصر نے ایک سماں تھا اسرائیل یہ

Jamiat Applauds Karnataka's Anti-Hate Speech Law

The Nation Must Unite in a Collective Fight Against Hate: Maulana Mahmood Madani

New Delhi : The President of Jamiat Ulama-i-Hind, Maulana Mahmood Madani, has welcomed the passage of a law by the Karnataka Assembly aimed at preventing hate speech and hate-based crimes.

He said that the Supreme Court of India has repeatedly observed that a "climate of hate prevails in the country," which poses a serious threat to social harmony, fraternity, and the democratic fabric of the nation.

Against this backdrop, the initiative taken by the Karnataka government is a positive and significant step towards promoting social cohesion and upholding the constitutional values enshrined in the Constitution of India.

Maulana Madani stated that Jamiat Ulama-i-Hind has consistently and for a long time been demanding the enactment of an



effective and comprehensive law to curb hate and hate-driven violence.

In this regard, the Jamiat has undertaken several initiatives both within and outside the courts, and has also established a dedicated department to address and counter the growing menace of hate. He recalled that it was on the petition filed

by Jamiat Ulama-i-Hind that the Supreme Court of India directed all states to ensure strict and effective implementation of the Tehseen Poonawalla Guidelines.

Referring to the April 2023 observations of the Supreme Court, Maulana Madani said that the Apex Court had categorically held that taking action

against hate speech is a constitutional responsibility of the state machinery. The Court further emphasized that authorities should not wait for formal complaints, but must act *suo motu* to prevent and curb such offences.

However, he expressed regret that despite these clear directions, most states have so far failed to

take concrete and effective steps. In this context, the proactive initiative taken by the Karnataka government offers a much-needed ray of hope.

Maulana Madani stressed that the success of any law against hate and violence does not depend merely on its enactment, but rather on its fair, transparent, and

non-discriminatory implementation.

He underlined the need for a careful and comprehensive study of the law, and for removing any ambiguities in its definitions, so that no future government is able to misuse it as a tool against minorities or other vulnerable sections of society.

Reiterating his resolve, Maulana Mahmood Madani said that Jamiat Ulama-i-Hind will continue its principled struggle across the country for peace, fraternity, and the supremacy of the Constitution.

Maulana also appealed to all state governments to enact effective laws against hate speech and hate-based crimes in the light of the directions issued by the Supreme Court, so that those who spread hatred and poison social harmony can be held accountable.

Karnataka Assembly Passes Hate Speech and Hate Crimes Prevention Bill Amid BJP Opposition

Bengaluru:

The Karnataka Legislative Assembly on Thursday passed the Hate Speech and Hate Crimes Prevention Bill, 2025, amid strong opposition and repeated disruptions by the Bharatiya Janata Party (BJP). The Bill proposes stringent penalties, including imprisonment of up to seven years and a fine ranging from Rs. 50,000 to Rs. 1 lakh, for individuals or organisations found guilty of promoting hatred.

Introducing the Bill, Home Minister G. Parameshwara said the legislation was necessary to curb the growing instances of hate speech and hate crimes in society. He noted that inflammatory statements made through speeches, books or electronic media could



have serious social consequences if left unchecked.

Participating in the debate, the Home Minister became emotional while sharing his personal experiences of discrimination during childhood. He emphasised that hatred based on religion, caste and gender was on the rise and needed to be addressed firmly through law. Stressing the importance of

constitutional values, he said true equality could be achieved only by fully implementing the Constitution drafted under the leadership of Dr B.R. Ambedkar.

According to the government, the law will apply not only to fresh content but also to previously published material that promotes hatred. The objective, Parameshwara said,

is to prevent the spread of divisive narratives and ensure social harmony.

Opposition Leader R. Ashoka strongly opposed the Bill, calling it an attack on freedom of expression. Questioning the need for such legislation 75 years after Independence, he alleged that the law could be misused to target political opponents and suppress dissent. He also claimed

that the Bill lacked adequate safeguards, including clear provisions for bail, and warned that journalists could be jailed under its provisions.

Ashoka described the Bill as a "political weapon" and cautioned the ruling party that it could be used against them in the future as well. He urged the government to exercise caution before enacting such a law. The debate witnessed heated scenes after Minister Byrathi Suresh made remarks concerning people from the coastal region, triggering protests from BJP legislators. The House saw repeated interruptions, with BJP MLA Sunil Kumar raising objections and pointing towards the Speaker. Despite the uproar, the government succeeded in passing the Bill.

حکومت نے منریگا پر چلا یا بلڈ وزر، غریبوں کے روزگار پر حملہ: سو نیا گاندھی

مہاتما گاندھی کا نام ہٹا دیا گیا بلکہ قانون کی ساخت اور طریقہ کارکوں بھی بغیر کسی وسیع مشاورت، بحث یا اپوزیشن کو اعتماد میں لیے کیکرٹنے طور پر بدیا گیا۔ وپیڈیو پیغام میں انہوں نے کہا کہ اب یہ فیصلہ دہلی میں پیش کر کیا جائے گا کہ کس کو، کہاں، لئتا اور کس طرح روزگار ملے گا، جو میں حقیقت سے مطابقت نہیں رکھتا۔ ان کے بقول میرزا یکا کو لانے اور نافذ کرنے میں کانگریس کا کوارض و رخا مگر یہ بھی پارٹی مفاد کی ایک نہیں رہی، بلکہ ملک اور عوام کے مفاد سے بڑی ایک جامع پالیسی تھی۔ سو یہاں گاندھی نے کہا کہ اس قانون کو کمزور کر کے حکومت نے کروڑوں سکانوں، مددوروں اور دہبی غریبیوں کے مفادات پر ضرب لگائی ہے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ اس کا لے قانون (وکست بھارت بھی رام بھی) کے خلاف کانگریس بھر پور جو جد کرے گی۔ آخر میں انہوں نے کہا کہ جیسے 20 برس فبل غریبیوں کے روزگار کے حق کے لیے آواز اٹھائی چکی، ویسے ہی آج بھی وہ اس جد و جد کے لیے پڑھمیں اور پارٹی کے تمام قائدین و کارکن عوام کے ساتھ کھڑے ہیں۔



A portrait of Sonia Gandhi, the President of the Indian National Congress. She is an elderly woman with long, dark grey hair and glasses, wearing a light-colored top. The background is a plain, light-colored wall.

قانون غریب طبق کیلے سہارا ثابت ہوا۔ سونیا گاندھی کے مطابق افسناک پہلو یہ ہے کہ حال ہی میں نہ صرف مزیگا سے

نئی دہلی: کانگریس پارلیمانی پارٹی (سی پی پی) کی جیت پر سن سویں گاندھی نے مزراگا (مہماں گاندھی نیشنل رورل اسکول پاٹمنٹ) کارپتی قانون میں ترمیم پر سخت رول نظارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ مرکزی حکومت نے اس قلائلی قانون پر بلڈوزر چلا دیا ہے۔ دہلی سے جاری ایک دیہی پیغام میں انہوں نے کہا کہ مزراگا مخصوص ایک سرکاری اسکیم نہیں بلکہ دیہی ہندوستان کے غریب، محروم اور بے زمین طبقات کے لیے روزگار کے قانونی حق کی ضمانت تھا، جسے کمزور کر دیا گیا ہے۔ سویں گاندھی نے یاد دلایا کہ تقریباً 20 برس قبل ڈاکٹر منوہن علی گنگوہی قیادت میں پارلیمنٹ نے مزراگا قانون کو اتفاق رائے سے منظور کیا تھا۔ ان کے مطابق یا یک انتلائی قوم تھا جس سے کروڑوں دیہی خاندانوں کو فائدہ پہنچا، اُنکی مکانی میں کی آئی، گرام پنجابیوں کو طاقت ملی اور مہماں گاندھی کے گرام سوراخ کے تصور کو عملی تکل دینے کی سمت مضمبوط پیش رفت ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ 11 برسوں میں موجودہ حکومت نے مزراگا کو کمزور کرنے کی مسلسل کوششیں کیں، حالانکہ کوڈو کے مشکل دور میں بھی

احمد آباد میں خاتون کو تھپڑ
مارنے پر پولیس اہل کار معطل

حمدآباد: بُجْرَات میں ایک پولیس اپارکار
ٹریکٹ کی خلاف ورزی پر خاتون کے ساتھ
بُجْرَے کے بعد میڈینے طور پر تھپر مارنے کے
الازم میں معتل کر دیا گیا ہے، حکام نے مخفی
کو بتایا۔ ڈپی کمشٹ آف پولیس (ٹریکٹ)
ویسٹ (بھاونا پیل) نے صافیوں کو بتایا، مل
ہبیدن کامپنی میں بھائی جمالا کو معتل کر دیا گیا
ہے یونکہ انہوں نے میڈینے طور پر ایک خاتون
کو ان کا شناختی کاڑہ گرانے پر تھپر
تھپر۔ حکام نے بتایا کہ یہ اتفاق جمع تھی ۹۷
و دسمبر کو سپن آیا جب ایک خاتون میڈینے طور
پالیٹی علاقے میں بغیر ہیلٹ کے دو ڈپر
کاڑہ پر سوار تھی۔ جالا نے خاتون کو ریکا
تو قوانین کی خلاف ورزی کرنے پر رُک دیا
صور تھال اس وقت بڑھ گئی جب خاتون
میڈینے طور پر کامپنی کا شناختی کاڑہ دیکھنے
مطاپہ کیا اور بد تیزی کی۔ ڈپی کمشٹ آف
پولیس پیل نے کہا، جب کامپنی نے اے
شناختی کاڑہ دکھایا تو خاتون نے میڈینے طور
اے سڑ میں پر گرا دیا۔ اس کے بعد کامپنی
مختعل ہو گی اور اسے تھپر مار دیا۔

‘دھوٹ چوری کر مودی حکومت نے لوگوں سے صاف ہوا پانی کا حق چھین لیا، دہلی میں بڑھتی آسودگی پر کانگریس کا تلاخ تبصرہ



پر شیئر کی ہے، جس میں پی ایم مودی کی ایک پرانی تقریر موجود ہے۔ اس میں وہ کہہ رہے ہیں ”نتخاب 100 شہروں میں آلوگی کم کرنے کے لیے ہم ایک پاک نظریہ کے ساتھ ایک مشن مودہ میں کام کرنے والے ہیں۔“ ویڈیو میں جیسے ہی پی ایم مودی کی تقریر ختم ہوتی ہے، ہندوستان میں آلوگی کے موجودہ حالات سے متعلق ایک خبر پیش کی جاتی ہے۔ اس میں بتایا جا رہا ہے کہ ”ہم نے دنیا بھر کے سب سے آلوہہ 50 شہروں کی لائیسنس چیک کی۔ ان 50 میں گیا ہے کہ ”حالات ایسے رہے تو ایک دن یہ (مودی حکومت) آپ سے فوڈ سیکرٹی قانون بھی چھین لیں گے۔ مودی حکومت کا صاف ایجاد ہے، عوام سے بھی حقوق چھین لوٹا کر عوام نہ کچھ کہہ سکے اور نہ ہی آواز اٹھا سکے۔ لیکن ملک سب دکھ رہا ہے۔ اس تاثنا شاہی کا سخت جواب دے گا۔“ اس یہ یو پوسٹ کے ساتھ کانگریس نے کیش گایا ہے ”زندگانی مودی ووٹ چوری کر عوام سے ان کے حقوق چھین رہے ہیں۔ ایک دیگر ویڈیو کانگریس نے اپنے نیکس میڈیل

دہلی میں آلو دگی اور کھرے
کے ساتھ سردی کا قہر!

تی دہلی: دہلی۔ این تی آر میں گہرے کہرے ساتھ ساتھ سردی نے بھی لوگوں کو پریشان کرنا شروع کر دیا ہے۔ شہری شدید سردی کی زد میں ہیں اس دوران ہندوستان کے محلے مومیتیں نے بھی پورے این تی آر کے لیے اورچ ارٹ جاری کیا ہے۔ ہفتہ کو موسم کی اچانک تبدلی کے باعث دن اور رات شدید سردی محسوس کی گئی۔ راجھاں دہلی میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 16 ڈگری سیلیسیس اور کم سے کم 6 ڈگری سیلیسیس رپارڈ کیا گیا جب کہ غازی آباد کا اے کیو آئی 441 تک پہنچ گیا جو صورتحال کی تکمیلی کو ظاہر کرتا ہے۔ دہلی۔ این تی آر میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اچانک موسم بدل گیا ہے اور چمچ سے ہی گہر کہرا چھاپا ہوا ہے۔ دن بھر ٹھنڈی ہوا کیں نے لوگوں کو کلپانے پر مجبور کر دیا۔

پنجاب میں لڑکی کا سر عام گولی مار کر قتل، علاقے میں سنسنی



گرفتار کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ مسلم آروروں کی تلاش کے لیے خصوصی ٹیکنیکیں تعمیل دے دی گئی ہیں۔ نہر کے آس پاس اور اطراف کے مواضعات میں چھاپے بارے چار ہے ہیں۔ ایں ایس پی ترن تارن نے یقین دیا کہ ملزمین کو جلد گرفتار کیا جائے گا اور کسی کی گھری کی تفییش کی جا رہی ہے۔ پولیس کی اضافی نفری تعینات کر کے علاقے میں سیکورٹی بڑھادی گئی ہے۔ پولیس اور انتظامیہ بڑھنے کی خبر پھیلتی ہی اہل خانہ اور رشیت داروں میں کہرام ٹھیک گیا۔ پورے علاقے میں خوف و ہراس کا ماحول تک تک جمل آروروں کو جلد سے جلد گرفتار کیا جا سکے۔ لوگوں نے پولیس سے جلد ملزمین کو

ترن تارن: پنجاب کے ضلع ترن تارن
س دل بدل دینے والا واقعہ پیش آیا ہے۔
مول پور نہر کے قریب سڑک کنارے کھڑی
ب لڑکی پر نامعلوم موٹر سائیکل سوار حملہ
وروں نے تاریخ پر فائزہ نگ کرو دی جس سے
وقع پر ہی اس کی موت ہو گئی۔ دن
ہاڑاۓ پیش آنے والی اس واردات سے
رے علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا
ہے۔ عین شاہدین کے مطابق لڑکی سڑک
کے کنارے کھڑی تھی کہ اچانک موٹر
سائیکلوں پر سوار و میں نو بجان وہاں پہنچے۔
بھوں ایک لفظ کہ بغیر لڑکی پر فائزہ نگ
سردی اور تیزی سے فرار ہو گئے۔ گولی لگتے
ہی متاثرہ زمین پر گر گئی۔ راگیوں نے
سے فوری طور پر قریبی اسٹیل پہنچایا لیکن
ہاں پہنچنے پر ڈاکٹروں نے اسے مردہ قرار
کے دیا۔ واقعہ کی اطلاع ملتے ہی ترن
رلن پولیس کی یتیم فوری طور پر جائے
صح پر پہنچیں۔ پولیس نے علاقے کو
لہیرے میں لے کر فیش شروع کر دی۔
ئے وقوع سے گولیوں کے خون اور دمگ
واپا کٹھ کر لیے گئے ہیں۔ حملہ اور وہ کی
ساخت اور ان کے موٹر سائیکل نمبر کا پتہ

اکھلیش پادو نے کہا اڑاوی بیچ گی تو دبلي بیچ گی! غیر ملکی چھوڑ یئے، ملکی سیاح بھی نہیں آئیں گے



نئی دہلی: ملک کے قدیم ترین پہاڑی سلسلوں میں سے ایک اراوی کی اوچانی پر میں نئی تحریف پر سیاں اور سماجی تناسع اور شہرت اختیار کر گیا ہے۔ ماحولیاتی کارکنوں کے احتجاج کے درمیان اپوزیشن نے بھی حکومت کو نشانہ بنایا ہے۔ سماجوادی پارٹی (ایس پی) کے صدر احمدیش یادو نے اسے دہلی اور این سی آر کے مستقل متعلق تکنین مسئلہ قرار دیتے ہوئے خبردار کیا ہے۔ واضح رہے کہ اراوی نتاز مدد برہار راست ماحولیات، آلووی پر قابو پانے اور عوامی تندریگی سے جڑا ہوا مانا جاتا ہے۔ ایس پی صدر احمدیش یادو نے اراوی پہاڑیوں کے بارے میں ایک بی پوسٹ شیئر کی ہے۔ جس میں انہوں نے لکھا

SAMLA Observes Minority Rights Day, Calls for Justice, Equality and Constitutional Morality



New Delhi: The South Asian Minorities Lawyers Association (SAMLA) marked Minority Rights Day at the India Islamic Cultural Centre, bringing together senior jurists, former judges, leading advocates, academics and human rights defenders. The programme, themed "Minorities' Rights – South Asian Perspective", focused on the growing challenges faced by minorities across the region. Over 40 senior lawyers were felicitated for completing 35 years of distinguished service to the legal profession.

Salman Khurshid, Senior Advocate and former External Affairs Minister, reaffirmed his

commitment to SAMLA's mission, stressing that coexistence rooted in morality, culture and shared humanity is the only ethical and sustainable response to social divisions. Drawing from John Rawls' *The Idea of Justice*, he underlined fairness, constitutional values and informed democratic participation.

Justice Iqbal Ansari, former Chief Justice of the Patna High Court, described equality as a timeless struggle and asserted that democracy survives on the principle of "agreeing to disagree." He cautioned against the political misuse of religion and emphasised that the Constitution remains India's strongest safe-

guard of freedom.

Senior Advocate of Supreme Court Chander Uday Singh warned against the growing "normalisation of persecution," recalling past communal targeting and condemning hate crimes, mob lynchings and the misuse of laws that criminalise interfaith relationships. He urged citizens to resist injustice by saying, "not in my name."

Sr. Advocate Nasir Aziz, President of SAMLA, pledged renewed resolve to defend minority rights across South Asia. Sr. Advocate Rakesh Khanna, former President of the Supreme Court Bar Association, highlighted con-

stitutional safeguards for minorities, while Mr. Wajahat Habibullah, former Chairman of the National Commission for Minorities, stressed the proactive role of minorities in nation-building.

During the programme, SAMLA adopted a comprehensive resolution reaffirming its commitment to protecting the religious, ethnic, linguistic and cultural rights of minorities in South Asia. A souvenir of SAMLA was released on the occasion. The welcome address was delivered by Feroz Khan Ghazi, who highlighted SAMLA's contributions and the continuing challenges faced by minorities.

Service as a Commitment

Central Bank of India Sets a Strong Example of Social Responsibility



New Delhi : On the auspicious occasion of its 115th Foundation Day, Central Bank of India's Delhi South Regional Office organised a special social service programme at Katyayani Balika Ashram, Jhandewalan, New Delhi, dedicated to the holistic welfare of tribal girls. The initiative reflected the Bank's continued commitment to social responsibility and inclusive development.

As part of the programme, essential items aimed at supporting

the girls' daily lives and education were distributed, including a washing machine, school bags, personal utility materials and other useful supplies. The initiative was designed to strengthen educational access and improve living conditions for the residents of the ashram.

The programme was held in the gracious presence of Shri Anil Agnihotri, Regional Head, and Shri Mandeep Kumar, Deputy Regional Head. Senior bank of

officials and staff members, including Shri Tarun Sharma, Ms Sarika and Ms Anubha, were also present and actively participated, adding meaningful value to the occasion.

Addressing the gathering, Shri Anil Agnihotri encouraged the girls to pursue education, self-reliance and a brighter future, while reaffirming Central Bank of India's steadfast commitment to the empowerment of all sections of society. He highlighted the importance of collective responsibil-



ity in building an inclusive and equitable future.

This initiative stands as a strong example of the Bank's dedication to corporate social responsibility, community welfare and inclusive growth. Marking 115 years of distinguished service, the programme vividly embodied the spirit of "banking with social engagement" and reinforced the Bank's enduring role in nation-building beyond financial services.

انڈین ملمس فارسول ریٹس (IMCR) کے عالی سطحی فندری ڈی.

Digitized by srujanika@gmail.com



نی دہلی: انہیں ملک مسلم فارسول رائٹس (IMCR) کے ایک اعلیٰ سطحی وفد نے آج نی دہلی میں ردازہ منی پیر اکٹھ گم (DMK) کی سینئر کرن پار یعنی محترم کمی موبیجنی سے ملاقات کی۔ یہ ملاقات خوشنگوار اور سببیتے ماحول میں ہوئی جس میں ملک کے موجودہ سماں جی ویساںی حالات، اقیقی حقوق بالخصوص مسلم کمیونٹی کو درپیش مسائل، اور تمل ناڈھ حکومت کی جانب سے ان مسائل کے درکار میں اختیاریگی کی ثابت پالیسیوں پر تفصیلی گفتگو ہوئی۔ وفد نے تمل ناڈھ حکومت کی جانب سے مسلم مسائل کے حل میں سبجیدہ وچیزی اور عملی اقدامات پر وزیر اعلیٰ ایم۔ کے۔ اسلام کی سبجیدہ کوششوں اور ان کی قیادت کا شکریہ ادا کیا، خصوصاً وزیر اعلیٰ کی قیادت میں اختیار کیے گئے وقف سے مختلف اقدامات کو سراہا، جن کے باعث ریاست میں اقیقتوں کا ایک حفظ اور باقراط ماحول میں مسماں یا ہے۔ محترم کمی موبیجنی نے اور وفد کی بات نہایت توجہ اور سبجیدگی سے سنی اور اس عزم کا اظہار کیا کہ ڈی ایم۔ کے ہمیشہ آئینی اقدام، سیکولرزم اور اقیقی حقوق کے تحفظ کے لیے پر عزم رہی ہے۔ انہوں نے مسلم کمیونٹی کے ساتھ ہر ممکن تعاون اور ان کے جائز مسائل کو پار یعنی مختلف فورم پر موثر انداز میں اٹھانے کی یقینی وہانی بھی کرائی۔ انہیں ملک مسلم فارسول رائٹس کے صدر محمد ادیب نے اس موقع پر ملک کے موجودہ حالات اور خاص طور پر وقف اماکن سے مختلف درپیش چالیج ہر کا تفصیلی ذکر کیا۔ انہوں نے وقف کے تحفظ اور اقیقی حقوق کے سلسلے میں تمل ناڈھ حکومت کے ثابت اور واضح وقف پر شکریہ ادا کرتے ہوئے امید ظاہر کی کہ دیگر ریاستیں بھی اسی طرز پر آئینی ذمہ داریوں کو نہجاں گی۔ ملاقات کے دوران IMCR کے رئیسی اور خزانی خلیفہ ایڈی و کیٹ فضیل احمد ایوبی اور سینئر صحافی انصار الہماری بھی موجود تھے۔ وفد نے اس بات پر زور دیا کہ موجودہ حالات میں جمہوری اور اسلامی اور سیاسی جماعتوں کے درمیان مکالمہ وفت کی اہم ضرورت ہے تاکہ ملک میں ہم آہنگی اور انساف اور سماجی توازن کو مضبوط کیا جاسکے۔ ملاقات کے اختتام پر دونوں جانب سے اس عزم کا اعادہ کیا گی کہ آئینی حقوق کے تحفظ کے لیے مشترک کوششیں کی جائیں گی۔ سیاست تماں اقیقتوں کے آئینی حقوق کے تحفظ کے لیے مشترک کوششیں کی جائیں گی۔

بنگلہ دیش میں صحافیوں پر حملہ اور گرفتاریاں ناقابلِ قبول، پریس کلب آف انڈیا کی شدید مذمت

اساں ہوتی ہے اور میدیا کو خاموش کرنے کی کسی بھی کوشش کو مقول نہیں کیا جاسکتا۔ پر یہں کلب آف ائمیا نے واضح کیا کہ صحافیوں کے خلاف تشدد، دھمکیاں، حملے یا ہر اسانی نہ صرف میدیا کی آزادی کے منافی ہیں بلکہ آئینی طور پر حاصل اظہار رائے کی آزادی اور قانون کی بالادستی کی بھی تکمیل خلاف ورزی ہیں۔ پر یہں کلب آف ائمیا کی صدر سینکیتیا بارواہ پیش روتی اور سکریٹی جرل افضل امام نے مطالباً کیا کہ ان واقعات میں ملوٹ عناصری فوری نشاندہی کی جائے اور ایک منصفانہ، غیر جانبدار اور تیز رفتار تحقیقات کے ذریعے مجرموں کو قانون کے کٹھرے میں لایا جائے۔ پر یہں کلب آف ائمیا نے یہاں اقوامی صحافتی تیظیموں اور انسانی حقوق کے اداروں سے بھی اپیل کی ہے کہ وہ بگذر دیں میں صحافیوں کی سلامت اور میدیا کی آزادی کے تحفظ کے لیے مؤثر کردار ادا کریں۔



عہدنا کارروائی کے طویل عرصے سے جیلوں میں رکھا گیا ہے۔ پی آئی نے ان تمام صحافیوں کی فوری اور میراث میں مشروط ہائی کام طالب کیا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ آزاد، خودختار وورثہ دار صحافت کی ہی جمہوری معاشرے کی بنیادی

نئی دہلی: (پر پیس ریلیز) پر پیس کلب آف انڈیا نے بگلہ دیش میں صاحبیوں کے خلاف بڑھتے ہوئے تشدیں، میڈیا اداروں پر حملوں اور صاحبیوں کی گرفتاریوں پر گہری تشویش کا اخبار کرتے ہوئے ان واقعات کی تخت الفاظ میں مذمت کی ہے پر پیس کلب آف انڈیا کی جانب سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ بگلہ دیش کے معروف انجمنات پر قوم آلو اور دی ڈی اسٹار کے فاتر پر پر تشدید حملے، توڑ پھوڑ اور آش زنی کے واقعات نہایت افسوسناک اور قابلی مذمت ہیں۔ بیان میں ایڈیٹر ٹرکٹ کے صدر اور روزنامہ نیو ایجنٹ کے ایڈیٹر، سینئر صاحبی نورل کبیر کو ہر اسال کیے جانے کے واقعات پر بھی شدید تشویش ظاہر کی گئی ہے پر پیس کلب آف انڈیا کے مطابق، بگلہ دیش میں عبوری حکومت کے اقتدار میں آنے کے بعد اب تک 100 سے زائد صاحبیوں کو قتل کے ازامات کے تحت گرفتاریا جا چکا ہے، جنہیں بغیر کسی

”نوایس آئی آئر“ پر، ملی میں قومی کنوشن کا انعقاد شہریوں کے آئینی حق رائے دہی کے تحفظ پر دیا ہے۔

ہے۔ سینئر دیکل پر شانت بھوشن اور سابق چیف ایکشن کمشنر ایس وائی فریشنی نے اپنے خلاف اکٹا اکٹھار کرتے ہوئے کہا کہ ایکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے، جس کی غیر جانبداری اور ساکھ تھخنڈ پوری جمہوری ساخت کے لیے ضروری ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ انتخابی نظام سے متعلق تمام فیصلے شفاف، قابل جائز اور عوام کے سامنے جو باہدہ ہوں۔ کوئی نہیں میں شریک سول سوسائٹی کے نمائندوں، ماہرین قانون، اساتذہ اور سماجی کارکنوں نے متفق طور پر اس بات پر زور دیا کہ شہری حقوق کے تحفظ کے لئے پر امن، آئینی اور جمہوری جدوجہد جاری رکھی جائے گی، اور بالغ رائے وہی کے حق پر کسی بھی قسم کے سمجھوتے کو قبول نہیں کیا جائے گا۔



در پیش موجو دو پیغمبر رضیلی اور کلمتی شفاقتی، جو بدلی اور عوامی اعتماد کا تنظیم کے وظروں است، انتخابی طریقہ کار اور شہری شمولیت کے معاملات میں کسی بھی قسم کی کوئی تباہی عوام کے حق کھڑانی کو کمرد رکھتی نہیں اور معرفت سماجی کارکن و مایہر معاشریت ٹھال دیرینے جو جمہوریت کو

نئی دہلی: شہری حقوق اور جمہوری اقدار کے تحفظ کے لیے سرگرم سول سوسائٹی نظمیوں کے پلیٹ فارم NO-SIR کے زیر اہتمام ”بانغ رائے دہی“ کے عالمی حق کے دفاع کے عنوان سے ایک اہم قومی کوئشن منعقد کیا گیا۔ اس کوئشن کا مقصد شہریوں کے آئینی حق رائے دہی کے تحفظ کو میکین بناانا اور ایکشن کمیشن آف اندھا کے بعض اقدامات پر اٹھنے والے میکین سوالات کو عوامی سطح پر جاگار کرنا تھا۔ کوئشن سے سابق حج صاحب جمیں مدن بی لوکر اور جمیں اے کے پٹنائک نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بانغ رائے دہی جمہوریت کی بنیاد سے اور اس سے کسی بھی قسم کی چیزیں چھاڑ آئینی روح کے منافی ہے۔ انہوں نے زور دیا کہ اتنا تعلیٰ میں

دیکتی سیاست کے درمیان انتخابات اور تاریک ہوتا مستقبل!

بِنَگَلَهْ دَلَیْش

کو خاموش کرانے کا مطلب ہی یہی ہے کہ آئے والا انتخابی عمل شفاف، آزاد اور قابل اعتماد نہیں رہے، بلکہ طاقتور ٹیکو کے زیر سایہ انجام پائے۔ بلکہ دلیش کی اس بگڑتی صورت حال پر بھارت کی تشویش بھی فطری ہے۔ نئی دلی نے ہادی کے ققل سے متفق ان اسلامات کو مسترد کرتے ہوئے بلکہ دلیش میں بڑھتی ہوئی بدہمی اور حملوں پر سنجیدہ خدمات کا اظہار کیا ہے۔ حکومت ہند کے پالیسی ساز حقوقوں کو اندر نیش ہے کہ اگر تشدد بے قابو ہو تو اس کے اثرات سرحد پار بھی پہنچ سکتے ہیں، جن میں غیر قانونی نقل مکانی، سرحدی سلامتی کے مسائل اور خطیں فرقہ وار انتتا کا بھیلا اور شامل ہے۔

بلکہ دلیش کا عدم استحکام درحقیقت پورے جنوبی ایشیا کے لیے خطرے کی گھنی ہے۔ ان تمام و اعقات نے ایک بنیادی اور خوفناک سوال کو مونو خر کرنے، کمزور کرنے یا مانتا ہج کو اپنی مرضی کے مطابق موڑنے کی ایک منظم سازش ہے؟ سیاسی ماہرین اس بات پر متفق نظر آتے ہیں کہ جب انتخابات کے قریب آتے ہی، اشتو، ادارہ جاتی بھر اور سماجی امتحان شدت اختیار کر جائے تو اسے محض اتفاق فراہمیں دیا جاسکتے۔ امن و امان کی بگڑتی صورت حال کو بنیاد بنا کر عام انتخابات میں تاثیر کا جواز پیدا کرنا یا ایک مخصوص سیاسی قوت کو ناگزیر حقیقت کے طور پر مسلط کرنا یا دونوں امکانات واضح طور پر موجود ہیں۔ ان سب کے نتیجے بھارت میں کاگزینی رکن پارلیمنٹ ششی تھرور کی صدارت میں قائم پارلیمنٹی کمیٹی نے بھی بھارت بلکہ دلیش تعلقات پر اپنی نویں رپورٹ پیش کی۔ انہوں نے بھی رپورٹ میں سیاسی عدم استحکام، سرحدی سلامتی اور تجارتی چیزیں کو دوڑھنے تعلقات کے لیے سب سے بڑا خطہ قرار دیا۔ علاوہ ازیں ڈھاکہ کیں جاری کیاں افریقی، آفیکیوں پر بڑھتے ہوئے حملوں اور بلکہ دلیش میں چین کی بڑھتی ہوئی موجودگی کے تنازع میں بھارتی پارلیمنٹ کی قائمہ کمیٹی نے حکومت ہند کو بھارت بلکہ دلیش تعلقات کے حوالے سے محتاط اور چوکنارہ میں کی داشت بھارت دی ہے۔



ہنکاں کر علاقائی حکماز آرائی میں تبدیل کرنے کی کی اس آگ میں سب سے زیادہ فلکیتیں نشانہ ہیں۔ جو تم کا ہاتھوں فلکیتی طبقے کے ایک نو قتل بگلکر دلیش کے اجتماعی ضمیر پر ایک بندگا اور ہے۔ یہ واقعہ اس تلخ حقیقت کو غاہر کرتا ہے کہ ہوئی ہے تو سب سے پہلے فلکیتی نشانہ بنتی ہیں والا شدید بھی انکار نہیں کہ اقیتوں پر ہونے والا شدید قانون کی کھلی خلاف و رزی ہے، بلکہ اسلامی افغانی سے، جو جان کے احترام، منہجی آزادی اور غیر



انظر الباری دفیقی
 پڑوئی ملک میں زبردست انتخابی مظاہر ہے۔
 کی سابق معزول وزیر اعظم شیخ حسین کو بڑی سی آیا
 ملک چھوڑ کر بھارت آنا پڑا۔ خیال کیا جا رہا تھا کہ
 بہتر ہو جائیں گے مگر حکم ایک سال کے اندر یہی بچا
 سب سے نازک، انتہائی خطرناک اور فصلہ کن من
 آکھڑا ہے، جہاں سیاست، تشدد، مذہب، طلبائی
 طاقتوں کے مفادات ایک دوسرے سے اس طریقے
 کہ یہاں کام مُستقل انتہائی تاریک اور حال خوفناک
 دیتا ہے۔ انتخابات کی تاریخوں کے اعلان نے بغایہ
 تحرک ضرور کیا ہے، تاہم زمینی حقائق اس کے
 آتے ہیں۔ انتہائی اعلان استحکام کا نہیں بلکہ بدیا
 مفہوم انتشار کے ایک منے مرحلے کا پیش نہیں بنتا
 ہے۔ انتہائی اعلان کے فوراً بعد سیاسی قوتوں کی
 بندی پاٹھوں کے اتحاد اور طبلاء گروہ کے انتہائی پیغام نے واضح
 اقتدار کی پر امن منتقلی کا مرحلہ نہیں، بلکہ طاقت
 ریاست اور ادویں پر کشتوں کی ایک ہم گیر جنگ۔
 اسٹوڈنٹس پالیسکس کی جارحانہ واپسی نے حالات کا
 ہے۔ طبلاء گروہوں کا خود کو ایک انتہائی قوت کے طور
 برداشت انتہائی سیاست میں داخل ہونے کا اعلان
 حق کے دائرے میں ضرور آتا ہے، مگر جب یہاں
 پکوڑ، بوٹ پاٹ، آگ زمینی انسانوں پر حملہ، رہ
 تصادم اور عوامی جان والی کائنات سے جڑا جو
 ہو جاتا ہے کہ آیا یہ سیاست ہے یا ریاست کو غیر ممکن
 مفہوم کو شد۔ اسی دوران مذہبی و سیاسی اتحاد کی تکمیل
 کی سیاست کو ایک اور خطرناک رخ کی طرف
 جماعت اسلامی کے ساتھ آٹھ مسلم جماعتوں